एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

एक्ज़िमिअस:
निर्यात लाभ

जून 2015
VOL. XXIX ISSUE II

इस अंक में

4 एक्ज़िम बैंक की प्रशिक्षण कार्यशाला – निर्यात क्षमताएं बढ़ाना
5 चीन के साथ भारत की व्यापार संभाव्यता
6 भारतीय टेक्सटाइल उद्योग: निष्पादन और संभावनाएं
7 एक्ज़िम बैंक की ऋण व्यवस्थाएं
8 तिमाही एक पुनरावलोकन
9 एक्ज़िम बैंक समाचार
10 भारतीय औषधि उद्योग
11 भारत की विदेश व्यापार नीति 2015-2020
12 एक्ज़िम बैंक की गतिविधियां और साहित्य समीक्षा
13 देश विदेश
14 मुद्रा संचलन
15 एक्ज़िम बैंक ने वर्ष 2014-15 में जोरदार कारोबार वृद्धि दर्ज की
16 भारतीय अर्थव्यवस्था - एक नजर
17 भारत का व्यापार निष्पादन

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का तिमाही प्रकाशन
www.eximbankindia.in

इकोवास क्षेत्र के साथ भारत का बढ़ता व्यापार

पश्चिमी अफ्रीकी राज्य आर्थिक समुदाय (इकोवास) अफ्रीका में एक प्रमुख क्षेत्रीय व्यापारिक गुट है. इसका गठन 16 पश्चिमी अफ्रीकी देशों द्वारा 28 मई, 1975 को लागोस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ. इकोवास के मौजूदा सदस्यों में बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोत' द वॉर, गाम्बिया, घाना, गीनिया, गीनिया-बिसाऊ, लाइबेरिया, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सिनेगल, सिरा लिओन तथा टोगो हैं. मारिटेनिया भी इसका सदस्य था किंतु अरब यूनियन में शामिल होने के लिए 2000 में यह इस गुट से अलग हो गया.

इकोवास में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता है. स्थानीय स्तर पर इनकी प्रारंभिक प्रोसेसिंग होती है. इकोवास एक महत्वपूर्ण व्यापारिक गुट है जिसका अफ्रीका के कुल भू-भाग में 17 प्रतिशत, कुल जनसंख्या में 30 प्रतिशत और कुल जीडीपी में 30 प्रतिशत हिस्सा है. इसके अलावा, सदस्य देशों द्वारा समान विकास नीतियां अपनाने से इस क्षेत्र में वृद्धि व विकास की अच्छी संभावनाएं हैं.

इकोवास क्षेत्र का जीडीपी 2004 के 192.1 बिलियन यूएस डॉलर के चार गुने से अधिक बढ़कर 2014 में 724.9 बिलियन यूएस डॉलर हो जाने का अनुमान है. इकोवास सदस्य राज्यों में नाइजीरिया सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका इकोवास के कुल जीडीपी में 79 प्रतिशत हिस्सा रहा, उसके बाद घाना तथा कोत-दि'वॉर का स्थान है.

इकोवास का विदेश व्यापार

कुल व्यापार की दृष्टि से अफ्रीका में इकोवास एक सबसे बड़ा व्यापारिक गुट है जिसका 2013 में अफ्रीका के कुल व्यापार में 20.7 प्रतिशत हिस्सा रहा. इस क्षेत्र के पास विश्व का लगभग 40 प्रतिशत बॉक्साइट भंडार, 5 प्रतिशत यूरेनियम भंडार तथा 4 प्रतिशत लौह एवं अयस्क भंडार है. यह क्षेत्र विश्व में तेल एवं गैस के कुछ बड़े भंडारों के लिए भी प्रसिद्ध है. नाइजीरिया के पास विश्व में सबसे बड़ा प्रमाणित प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम भंडार है और यह कच्चे तेल का एक अग्रणी उत्पादक एवं निर्यातक भी है. इस अफ्रीकी व्यापारिक गुट से अफ्रीका के भीतर और अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के साथ क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने में भी सहायता मिली है. इकोवास देशों का कुल व्यापार 2004 के 86.8 बिलियन यूएस डॉलर से तीन गुना बढ़कर 2013 में 250 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है. इकोवास का वैश्विक निर्यात 2004 के 53.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2013 में 139.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है. तदनुसार, कुल अफ्रीकी निर्यात में इकोवास का हिस्सा भी 2004 के 22.4 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 24.2 प्रतिशत हो गया. नाइजीरिया, घाना तथा कोत' दि वॉर क्षेत्र के मुख्य निर्यातक हैं. इकोवास का वैश्विक आयात 2004 के 33.1 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2013 में 110.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है. कुल अफ्रीकी आयात में इकोवास का हिस्सा भी 2004 के 15.6 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में 17.9 प्रतिशत हो गया. नाइजीरिया, लाइबेरिया, कोत' दि वॉर, घाना तथा सिनेगल क्षेत्र के मुख्य आयातक हैं. इकोवास के व्यापार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सदस्य देशों में व्यापार संतुलन में भारी अंतर है. इकोवास क्षेत्र सामान्यत: व्यापार अधिशेष रखता है, हालांकि अधिकांश सदस्य देश व्यापार घाटा रखते हैं. व्यापार अधिशेष 2004 के 20.6 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2013 में 29 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है. क्षेत्र के पन्द्रह देशों में से सिर्फ तीन देशों अर्थात नाइजीरिया, घाना तथा सीअरा लिओन ने 2013 में अधिशेष दर्ज किया जो शेष सदस्य देशों के व्यापार घाटे से अधिक रहा.

15 दिसंबर, 2014 में पश्चिम अफ्रीकी राज्य प्रमुखों तथा सरकारों ने आर्थिक विकास तथा क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय शुल्कों तथा करों को सरल एवं कारगर बनाने के लिए औपचारिक रूप से सीईटी का शुभारंभ किया और उसे 1 जनवरी, 2015 से लागू किया.

इकोवास देशों के साथ भारत के व्यापार संबंध

इकोवास के साथ भारत का कुल व्यापार 2004 के 1.9 बिलियन यूएस डॉलर से लगभग 12 गुना बढ़कर 2013 में 22.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया **(तालिका)**. इकोवास को भारत का कुल निर्यात 2004 के 1.2 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2013 में 7.0 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है जो इस अवधि में छ: गुनी वृद्धि दर्शाता है. इकोवास से भारत का कुल आयात भी 23 गुना वृद्धि दर्शाते हुए 0.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 15.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है. फलस्वरूप, इकोवास के साथ भारत का

व्यापार संतुलन, जो 2004 में 0.5 बिलियन यूएस डॉलर के अधिशेष में था, हाल के वर्षों में नकारात्मक हो गया है. 2013 में इकोवास के साथ भारत का व्यापार घाटा 8.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा.

भारत इकोवास का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बनता जा रहा है. 2013 में इकोवास के आयात में भारत का हिस्सा 2004 के 1.6 प्रतिशत से बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया. इसके अलावा, इकोवास के कुल निर्यात का लगभग 10.8 प्रतिशत भारत को जाता है जो 2004 के 0.9 प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक है और इस प्रकार भारत इकोवास के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थान है. इसी अवधि में, भारत के वैश्विक आयात में इकोवास का हिस्सा भी 2004 के 0.7 प्रतिशत से बढ़कर 2013 में लगभग 3.4 प्रतिशत हो गया, जबकि भारत के कुल निर्यात का 2.1 प्रतिशत 2013 में इकोवास क्षेत्र को गया जो 2004 के 1.6 प्रतिशत से अधिक है.

नाइजीरिया इकोवास क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है जिसका 2013 में भारत के कुल निर्यात में लगभग 41.4 प्रतिशत हिस्सा रहा. इकोवास में भारत के अन्य प्रमुख निर्यात बाजारों में घाना, बेनिन, सिनेगल तथा टोगो शामिल हैं. नाइजीरिया भारत से वाहनों, मशीनरी तथा इलेक्ट्रिकल उपकरणों के निर्यात के लिए इकोवास क्षेत्र में अग्रणी बाजार है, जबकि घाना भारत से औषधियों, लौह एवं इस्पात, मशीनरी, वाहन तथा इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए प्रमुख निर्यात बाजार है. बेनिन भारत से अनाजों के निर्यात के लिए अग्रणी बाजार है जिसका इकोवास को भारत से अनाजों के कुल निर्यात में 43.4 प्रतिशत हिस्सा रहा.

इकोवास को भारत के शीर्ष पांच प्रमुख निर्यातों अर्थात अनाज, फार्मास्युटिकल्स, वाहन, मशीनरी तथा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का 2013 में इकोवास को भारत के कुल निर्यात में 52 प्रतिशत संयुक्त हिस्सा रहा. इकोवास को भारत के निर्यात की अन्य प्रमुख मदों में लोहा एवं इस्पात, खनिज ईंधन, प्लास्टिक तथा उसकी वस्तुएं, कॉटन तथा लौह एवं इस्पात से निर्मित वस्तुएं शामिल हैं.

इकोवास भारत से अनाजों के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान के रूप में उभर रहा है. 2004-2013 की अवधि के दौरान, भारत से अनाजों के वैश्विक निर्यात में आठ गुनी वृद्धि हुई और यह 1.4 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 11.4 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जबकि भारत से इकोवास को निर्यात में 11 गुनी वृद्धि हुई और यह 120.3 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 1.3 बिलियन यूएस डॉलर हो गया, जिसमें प्रमुख बाजार बेनिन, सिनेगल, लाइबेरिया तथा कोत' दि वार रहे. 2013 में भारत से अनाजों के कुल वैश्विक निर्यात में इकोवास का हिस्सा 11.6 प्रतिशत रहा. बेनिन भारत से अनाजों के निर्यात के लिए पांचवां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थान है (ईरान, सऊदी अरब, बांग्लादेश तथा यूएई के बाद) जिसका भारत के वैश्विक निर्यात में 5.1 प्रतिशत हिस्सा रहा. जहां तक फार्मास्युटिकल्स का संबंध है, इकोवास को भारत का निर्यात 2004 के 154.5 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2013 में 753.7 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है. 2013 में भारत के निर्यात में इस क्षेत्र का 6.3 प्रतिशत हिस्सा रहा. नाइजीरिया इकोवास में अग्रणी बाजार है, उसके बाद घाना, बेनिन, बुर्किनो फासो का स्थान रहा. इकोवास भारत से वाहनों के निर्यात के लिए भी एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभरा है जहां भारत का निर्यात 2004 के 59.9 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2013 में 650.4 मिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंच गया और भारत से वाहनों के निर्यात में इसका 4.7 प्रतिशत हिस्सा रहा. इकोवास क्षेत्र में सबसे बड़े बाजार नाइजीरिया, घाना, गीनिया तथा कोत' दि वॉर हैं.

जहां तक आयात का संबंध है, नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत है, उसके बाद घाना तथा कोत' दि वॉर का स्थान है. नाइजीरिया भारत के खनिज ईंधन के आयात के लिए चौथा सबसे बड़ा वैश्विक आयात स्रोत (सऊदी अरब, ईराक तथा कतर के बाद) है.

इकोवास के साथ भारत का व्यापार, 2004-2013 (बिलियन यूएस डॉलर)

मद	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
इकोवास को भारत का कुल निर्यात	**1.2**	**1.7**	**1.9**	**2.9**	**2.9**	**2.9**	**3.5**	**5.4**	**6.0**	**7.0**
इकोवास के कुल आयात में % हिस्सा	2.9	3.3	3.6	3.8	2.3	3.1	4.0	3.7	5.0	5.0
भारत के कुल निर्यात में % हिस्सा	1.6	1.7	1.6	2.0	1.6	1.6	1.6	1.8	2.1	2.1
इकोवास से भारत का कुल आयात	**0.7**	**0.9**	**6.6**	**8.5**	**11.9**	**6.7**	**11.6**	**15.7**	**16.0**	**15.7**
इकोवास के कुल निर्यात में % हिस्सा	0.9	0.8	7.7	5.7	8.1	6.7	8.6	9.5	12.1	10.8
भारत के कुल आयात में % हिस्सा	0.7	0.7	3.7	3.9	3.8	2.5	3.3	3.4	3.3	3.4
इकोवास के साथ भारत का कुल व्यापार (निर्यात +आयात)	**1.9**	**2.7**	**8.6**	**11.5**	**14.8**	**9.6**	**15.2**	**21.1**	**22.0**	**22.7**
इकोवास के साथ भारत का व्यापार संतुलन	**0.5**	**0.8**	**-4.7**	**-5.6**	**-9.0**	**-3.9**	**-8.1**	**-10.3**	**-10.1**	**-8.7**

टिप्पणी : 2006 से आयात आंकड़े में तेल आयात शामिल हैं
स्रोत: यूएन कॉमट्रेड से प्राप्त आईटीसी ट्रेडमैप

नाइजीरिया से भारत के खनिज ईंधन आयात में कच्चे तेल की प्रधानता है. खनिज ईंधन, (जिसमें मुख्यत: कच्चे तेल की प्रधानता है.) इकोवास से भारत के आयात बास्केट की लिए सबसे बड़ी मद है जिसका 2013 में इकोवास से कुल आयात में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा रहा. भारत के सबसे बड़े गैर-तेल आयात में खाद्य फल एवं नट्स (जिसका इकोवास से भारत के आयात में 3.9 प्रतिशत हिस्सा रहा) लकड़ी तथा उसकी वस्तुएं और कॉटन शामिल हैं.

इकोवास देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन

भारत और इकोवास के बीच द्विपक्षीय व्यापार में इकोवास के साथ भारत का व्यापार घाटा रहा है जो 2004 के 1.9 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2013 में 22.7 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है.

इकोवास के साथ भारत का व्यापार संतुलन, जो 2004 में 0.5 बिलियन यूएस डॉलर के अधिशेष में था, उसके बाद घाटे में चला गया और 2006 में (-) 4.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2013 में (-) 8.7 बिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंच गया. इकोवास सदस्यों में, भारत नाइजीरिया, गीनिया, गीनिया-बिसाऊ तथा केप वर्डे के साथ व्यापार घाटा रखता है, जबकि बेनिन, घाना, सिनेगल, टोगो, लाइबेरिया, सीयरा लियोन, बुर्किना फासो, नाइजर, माली, गाम्बिया तथा कोत' दि वॉर के साथ इसका व्यापार अधिशेष है.

इकोवास के साथ भारत के व्यापार घाटे की मुख्य वजह नाइजीरिया तथा गीनिया से कच्चे पेट्रोलियम आयात की बढ़ती मात्रा है. गीनिया बिसाऊ के साथ भारत का व्यापार घाटा मुख्यत: खाद्य फल, गिरी (मुख्यत: काजू) के उच्च आयात के कारण है, जबकि केपवर्डे के साथ व्यापार घाटा बड़ी मात्रा में लौह एवं इस्पात (मुख्यत: धात्विक अवशिष्ट तथा स्क्रैप) के आयात के कारण है.

इकोवास देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंध बढ़ाने की संभाव्यता

इकोवास क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार को और बढ़ाने के लिए तथा साथ ही बढ़ते घाटे को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में इकोवास के उन देशों के साथ भारत की निर्यात संभाव्यता पर फोकस करना होगा जिनके साथ भारत का बड़ा तथा बढ़ता व्यापार घाटा है. ऐसी रणनीति से इकोवास को भारत का निर्यात बढ़ाने के समग्र प्रयासों को भी बल मिलेगा.

भारत की निर्यात संभाव्यता और इकोवास क्षेत्र में मौजूदा मांग के आधार पर इकोवास क्षेत्र को भारत के निर्यात की संभाव्य मदों में मुख्यत: मशीनें, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वाहन, जहाज तथा अन्य समरूपी संरचनाएं, खनिज ईंधन तथा आसवन उत्पाद, अनाज, लौह एवं इस्पात की वस्तुएं, मछली, चीनी तथा कन्फेक्शनरी, डेरी उत्पाद तथा अंडे, तेल एवं इत्र, प्लास्टिक तथा उसकी वस्तुएं, नमक एवं सल्फर स्टोन, पशु एवं वनस्पति तेल, मांस, सिरैमिक उत्पाद, अकार्बनिक रसायन, फार्मास्युटिकल उत्पाद, आटा, स्टार्च तथा दूध से बनी वस्तुएं, पेपर व पेपरबोर्ड, रबड़ एवं उसकी वस्तुएं, कॉटन, विविध खाद्य सम्पाक, लोहा एवं इस्पात, मिलिंग उत्पाद तथा माल्ट, स्टार्च, अन्य टेक्सटाइल वस्तुएं तथा पेय एवं सिरका शामिल हैं.

इकोवास क्षेत्र में भारतीय निर्यात-आयात बैंक

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) 1982 में अपनी स्थापना के समय से ही पश्चिमी अफ्रीका में भारतीय कंपनियों को ऋण प्रदान कर और विभिन्न सहयोगी कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर कर क्षेत्र में निवेश के लिए उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता रहा है. पश्चिम अफ्रीका में एक्ज़िम बैंक के वित्तपोषण कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी), परियोजना निर्यात के लिए सहायता, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) के अंतर्गत क्रेता ऋण तथा विदेशी संयुक्त उद्यमों के लिए वित्त शामिल हैं.

अफ्रीका में एक्ज़िम बैंक के दो प्रतिनिधि कार्यालय हैं जो अदिस अबाबा, ईथियोपिया और जोहॉन्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं. ये कार्यालय अफ्रीकी देशों के साथ बैंक को व्यापार को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. प्रतिनिधि कार्यालय विभिन्न संस्थाओं जैसे अफ्रीकी विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ साऊथ अफ्रीका लि., क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे पश्चिम अफ्रीकी विकास बैंक (बीओएडी), अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक तथा पूर्वी एवं दक्षिण अफ्रीकी व्यापार एवं विकास बैंक (पीटीए बैंक) और साथ ही क्षेत्र में भारतीय दूतावासों से परस्पर संवाद करते हैं और इस प्रकार अफ्रीकी क्षेत्र में बैंक की पहलों से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं. एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन 'इकोवास के साथ भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ाना : एक संक्षिप्त विश्लेषण' में भारत से इकोवास को संभाव्य निर्यात पण्यों का विस्तृत विश्लेषण, (6 डिजिट एचएस कोड तक) किया गया है.

अफ्रीका – भारत सहभागिता दिवस

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) तथा फिक्की (भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ) ने विशेषकर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक तथा निजी सहभागिता में अफ्रीका के साथ भारत के विकासात्मक अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य से अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) समूह की वार्षिक बैठक के हिस्से के रूप में 27 मई, 2015 को अबिदजान, कोत' दि वॉर में अफ्रीका– भारत सहभागिता दिवस का आयोजन किया.

25 भारतीय कंपनियों से उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने इस कार्यक्रम में भाग लेने और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने और इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेषकर ऊर्जा तथा परिवहन क्षेत्रों के विकास में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए अबिदजान का दौरा किया.

इस अवसर पर आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अवर सचिव श्री दिनेश शर्मा द्वारा एक्ज़िम बैंक के प्रकाशन 'इकोवास के साथ भारत के व्यापार संबंधों को बढ़ाना: एक संक्षिप्त विश्लेषण' का विमोचन भी किया गया.

अफ्रीका-भारत सहभागिता दिवस अफ्रीकी विकास बैंक की वार्षिक सभा का नियमित हिस्सा हो गया है और यह अफ्रीका-भारत के बीच सहभागिता को बढ़ाने के लिए विपुल संभाव्यता भी प्रदर्शित करता है.

एक्ज़िम बैंक की प्रशिक्षण कार्यशाला – निर्यात क्षमताएं बढ़ाना

भारतीय निर्यात-आयात बैंक भारत के व्यापार तथा निवेश का वित्तपोषण करने, उसे सुगम बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित एक शीर्ष वित्तीय संस्था है. दुतरफा व्यापार तथा निवेश के वित्तपोषण के अलावा, एक्ज़िम बैंक एक संवर्धनात्मक भूमिका भी अदा करता है और भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमता तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता सृजित करने तथा उसे बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है. बैंक लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) सहित विभिन्न भारतीय कंपनियों को उनके भूमंडलीकरण प्रयासों में सहायता प्रदान करता है. एक्ज़िम बैंक ने सूक्ष्म एवं ग्रामीण उद्यमों, एनजीओ, ट्रस्टों, सोसायटियों तथा सहकारी समितियों, (जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्यात उन्मुखता के साथ आजीविका निर्माण कार्यकलापों में लगी हैं) को सहायता प्रदान करने के लिए उन्हें एसएमई के दायरे में शामिल किया है. बैंक की इन गतिविधियों को ग्रासरूट उद्यम एवं विकास (ग्रिड) समूह के अंतर्गत चलाया जा रहा है.

ग्रिड कार्यकलापों में ग्रासरूट पहलों / प्रौद्योगिकियों (विशेषकर निर्यात संभाव्यता वाली) को समर्थन और देश भर में शिल्पकारों / उत्पादक समूहों / क्लस्टरों / छोटे उद्यमों / एनजीओ को सहायता प्रदान करना शामिल है ताकि इन इकाइयों से निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान कर उनकी लाभप्रदता बढ़ाई जा सके. ग्रुप उत्पाद विकास के प्रत्येक चरण अर्थात मौजूदा उत्पादों के लिए आधुनिक डिजाइन व पैकेजिंग क्षमता निर्माण तथा विस्तार, विशाखन और निर्यात में हर तरह की सहायता प्रदान कर समग्र दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में कार्य करता है और इस प्रकार उद्यमों को निर्यात बाजारों में पहुंचने में बाधक मुद्दों का समाधान करता है.

ग्रिड के कार्यक्रम / योजनाएं पारंपरिक शिल्पकारों, ग्रामीण उद्यमियों तथा छोटे व्यावसायिकों के लिए नए अवसर उत्पन्न कर समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. ग्रिड के अंतर्गत सहायता का एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

- विभिन्न संगठन जैसे क्लस्टर / एसएचजी / को-ऑपरेटिव्स / एनजीओ / उत्पादक समूह / उद्यम / कंपनियां आदि कच्चे माल गोदाम की स्थापना, साझा सुविधा केंद्र, मशीनों या अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए एक्ज़िम बैंक से ऋण सहायता ले सकते हैं.
- विदेशी मुद्रा तथा भारतीय रुपये दोनों में पोतलदान-पूर्व तथा पश्चात ऋण;
- उत्पादक समूहों / शिल्पकारों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम.

उक्त सभी उत्पाद क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, बाजार पहुँच, प्रशिक्षण आदि कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं. एक्ज़िम बैंक संगठनों की जरूरतों के मुताबिक भारतीय रुपये तथा विदेशी मुद्रा दोनों में त्वरित तथा प्रतिस्पर्धी वित्त प्रदान करता है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनने में उनकी सहायता करता है.

क्षमता निर्माण कार्य के एक भाग के रूप में, एक्ज़िम बैंक ने थुहा, पटियाला, पंजाब में तथा उसके आस-पास के गांवों की चुनिंदा 30 महिला मास्टर शिल्पियों के लिए जुलाई 2015 से प्रारंभ करते हुए 4 महीने की कार्यशाला आयोजित करने के लिए फुलकारी हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप इंडस्ट्रियल सोसायटी लिमिटेड (पीएच डब्ल्यू सीएस) के साथ सहभागिता की. कार्यशाला में दो क्षेत्र शामिल हैं अर्थात् (क) प्रशिक्षण आधुनिक डिज़ाइनिंग के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर उत्पाद विकास और (ख) महिला शिल्पियों को उन्नत मशीनों (जुकी मशीनों) के प्रयोग के बारे में तकनीकी जानकारी देना ताकि उत्पादन में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों दृष्टियों से सुधार हो. इस कार्यशाला से महिला शिल्पी देशी तथा निर्यात बाजार दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने में समर्थ हो सकेंगी. जिससे उनके आय स्तर में सुधार होगा. इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शनी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुभवों को साझा करना, विचार-विमर्श और फुलकारी कला का प्रयोग करते हुए हैंडीक्राफ्ट के लिए उपयोगिता आधारित सामान विकसित करना है.

1997 में स्थापित पीएचडब्ल्यूसीएस महिलाओं को सशक्त बनाने और पंजाब की फुलकारी कढ़ाई की निर्जीव कला का पुनरुत्थान करने के उद्देश्य से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत एक गैर-सरकारी संगठन है. अपनी स्थापना से ही पीएचडब्ल्यूसीएस ग्रामीण समुदाय के उपेक्षित वर्गों की महिलाओं के लिए आय-निर्माण तथा कल्याण की दिशा में कार्य कर रहा है.

पीएचडब्ल्यूसीएस वर्तमान में पंजाब के पटियाला जिले में 12-15 महिलाओं के 150 स्वयं सहायता प्राप्त समूहों (एसएचजी) के साथ कार्य कर रहा है. पीएचडब्ल्यूसीएस हस्तनिर्मित फुलकारी क्राफ्ट जैसे स्कार्व, स्टोल, जैकेट, सूट, दुपट्टा, बेडशीट तथा पिलो कवर, ऑफिस फोल्डर के उत्पादन में लगा है. ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं इस कार्य को करती हैं.

बैंक डिज़ाइन विकास कार्यशालाएं आयोजित करके देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए ग्रामीण शिल्पियों तथा हस्त शिल्पियों को सहायता प्रदान कर रहा है. यह प्रशिक्षण पंजाब के पटियाला जिले के थुहा गांव की महिला मास्टर शिल्पियों को प्रदान किया जा रहा है जो आगे अन्य अकुशल या अर्ध कुशल महिला शिल्पियों को प्रशिक्षित करेंगी. इसका लाभ तथा प्रभाव काफी व्यापक होगा. इस कार्यशाला से इस शिल्प को देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति प्राप्त करने में सहायता मिलेगी.

हाल के वर्षों में चीन विश्व के अग्रणी निर्यातक के रूप में उभरा है वर्ष 2011 में वैश्विक निर्यात में चीन का 10.4 प्रतिशत हिस्सा था जो 2014 में 12.5 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गया है. विश्व के अग्रणी निर्यातक के रूप में चीन ने जर्मनी तथा यूएसए दोनों को पछाड़ा है. जहां तक आयात का संबंध है, चीन 2014 में वैश्विक आयात में 10.4 प्रतिशत हिस्से के साथ यूएसए के बाद दूसरा सबसे बड़ा आयातक रहा है.

चीन का व्यापार रुझान

चीन का वैश्विक व्यापार 2005 के 1422 बिलियन यूएस डॉलर से 3 गुने से अधिक बढ़कर 2014 में 4305 बिलियन यूएस डॉलर (वैश्विक निर्यात 2014 में 2343 बिलियन यूएस डॉलर तथा आयात 1962 बिलियन यूएस डॉलर) रहा. फलस्वरूप, चीन के व्यापार अधिशेष में पिछले दशक में तीव्र वृद्धि हुई और यह 2005 के 102 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2014 में 381 बिलियन यूएस डॉलर हो गया जिसमें हांग कांग तथा यूएसए अग्रणी व्यापारिक भागीदार रहे जिनके साथ चीन सर्वाधिक व्यापार अधिशेष रखता है.

भारत के साथ चीन का व्यापार

द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में तारतम्य प्रदर्शित करते हुए भारत और चीन के बीच कुल व्यापार 2005 के 18.7 बिलियन यूएस डॉलर से लगभग चार गुना बढ़ते हुए 2014 में 70.6 बिलियन यूएस डॉलर हो गया जो चीन से भारत को निर्यात और चीन द्वारा भारत से आयात दोनों की बढ़त की बदौलत है **(चार्ट)**. भारत को चीन का निर्यात 2014 में 54.2 बिलियन यूएस डॉलर तथा भारत से चीन का आयात 16.4 बिलियन यूएस डॉलर रहा. जहां 2014 में चीन के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा 2.3 प्रतिशत रहा. वहीं चीन के वैश्विक आयात में भारत का हिस्सा 2010 के 1.5 प्रतिशत से घटकर 2014 में 0.8 प्रतिशत रह गया. चीन भारत के साथ व्यापार अधिशेष रखता है जो 2005 से (-) 0.8 बिलियन यूएस डॉलर के घाटे से बढ़कर 2014 में लगभग 38 बिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है.

भारत के साथ चीन का व्यापार – प्रमुख पण्य

इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा मशीनें एवं बॉयलर चीन द्वारा भारत को निर्यात की दो सबसे बड़ी मदें हैं जिनका 2014 के दौरान भारत को चीन के कुल निर्यात में लगभग 39 प्रतिशत का संयुक्त हिस्सा रहा. भारत चीन की प्रमुख निर्यात मदों के लिए एक अग्रणी गंतव्य स्थान के रूप में उभरा है. उदाहरण के लिए भारत चीन के प्रमुख निर्यातों जैसे आर्गेनिक रसायनों (2014 में 13.7 प्रतिशत हिस्सा) तथा उर्वरकों (26.2 प्रतिशत हिस्सा) के लिए सबसे बड़ा बाजार है; प्लास्टिक तथा प्लास्टिक वस्तुओं (3.3 प्रतिशत हिस्सा) के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार; मशीनों एवं बॉयलरों (2.5 प्रतिशत हिस्सा) तथा लौह एवं इस्पात (4.2 प्रतिशत हिसा) के लिए छठा सबसे बड़ा बाजार; और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (1.9 प्रतिश्त हिस्सा) के लिए 10 वां सबसे बड़ा बाजार है.

भारत से चीन द्वारा आयात की जाने वाली प्रमुख मदों में मुख्यत: कॉटन, पर्ल तथा बहुमूल्य रत्न तथा तांबा एवं उसकी वस्तुएं शामिल हैं जिनका 2014 के दौरान भारत से चीन के कुल आयात में लगभग आधा हिस्सा (क्रमश: 19.6 प्रतिशत, 15.4 प्रतिशत और 14.3 प्रतिशत हिसा) रहा है. वैश्विक रूप से चीन की प्रमुख आयात मदों की यदि बात करें तो भारत 2014 में चीन द्वारा कपास के आयात (चीन के आयात में 25.2 प्रतिशत हिस्सा) के लिए अग्रणी वैश्विक स्रोत रहा; नमक, सल्फर तथा सीमेंट के लिए यह दूसरे सबसे बड़े स्रोत (15.4 प्रतिशत हिस्सा) के रूप में उभरा ; जबकि मोती तथा बहुमूल्य रत्नों के लिए चौथे सबसे बड़े स्रोत (6 प्रतिशत हिस्सा) और तांबा व उसकी वस्तुओं के लिए 7वें सबसे बड़े स्रोत (4.9 प्रतिशत हिस्सा) के रूप में उभरा है.

द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए संभाव्य क्षेत्र

हालांकि भारत ने चीन द्वारा आयात की जाने वाली कुछ मदों के वैश्विक आयात में अपेक्षाकृत अच्छा हिस्सा हासिल कर लिया है किन्तु भारत की वैश्विक निर्यात क्षमता और चीन की आयात मांग को देखते हुए अभी भी इसमें काफी संभावनाएं हैं और भारत चीन का व्यापार बढ़ सकता है. भारत से चीन को निर्यात की जाने वाली प्रमुख संभाव्य मदों में इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (एचएस-85); पेट्रोलियम उत्पाद (एचएस-27); मशीनें एवं बॉयलर (एचएस-84); ऑप्टिकल, फोटो, तकनीकी, चिकित्सा उपकरण (एचएस-90); रेलवे, ट्रामवे से इतर वाहन (एचएस-87) तथा प्लास्टिक एवं उसकी वस्तुएं (एचएस-39); लौह एवं इस्पात (एचएस-72) तथा औषधि उत्पाद (एचएस-30) आदि हैं जिनके लिए अभी भी निर्यात की काफी अच्छी गुंजाइश है.

भारत के साथ चीन का व्यापार, 2005-2014 (बिलियन यूएस डॉलर)

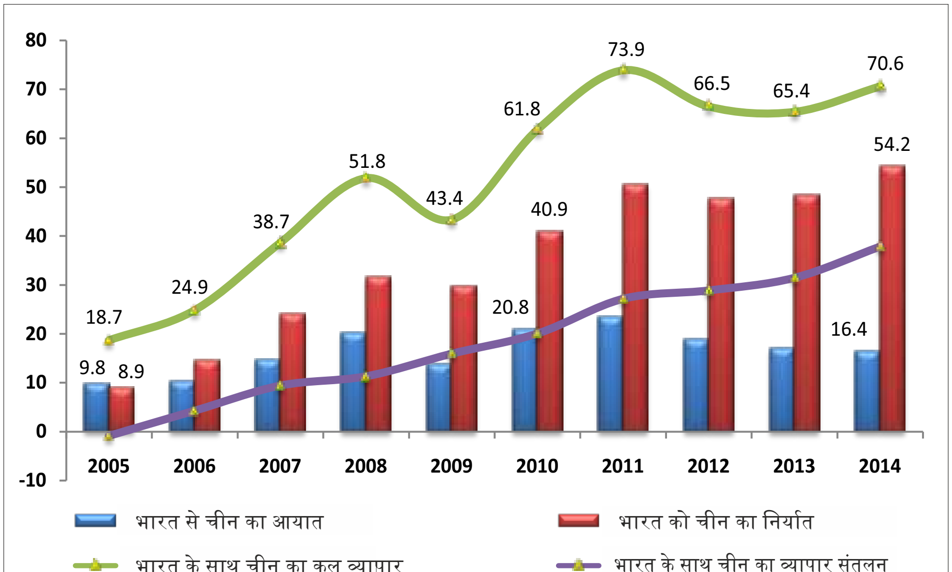

स्रोत: आईटीसी, जिनेवा, यूएन कॉमट्रेड सांख्यिकीय तथा एक्ज़िम बैंक विश्लेषण पर आधारित

टेक्सटाइल तथा वस्त्र उद्योग का भारत के आर्थिक विकास पर जबर्दस्त प्रभाव है क्योंकि कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है. औद्योगिक उत्पादन, रोजगार एवं निर्यात में अपने योगदान के माध्यम से यह उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. भारत में परिधान बाजार का आकार 2013 में वैश्विक बाजार आकार का 4 प्रतिशत था जिसके 2025 तक 9 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच जाने की उम्मीद है.

उद्योग का कार्य-निष्पादन

ऐसे समय में जब कई उद्योगों के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वृद्धि नकारात्मक में चली गई है, टेक्सटाइल के लिए आईआईपी 2013-14 में 4.2 प्रतिशत और बाद में 2014-15 में 2.6 प्रतिशत बढ़ा. 2014-15 में पहनावा परिधान फर की ड्रेसिंग तथा डाइंग के लिए आईआईपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही.

2014-15 में भारत में फाइबर तथा यार्न की अधिकांश श्रेणियों (मानव निर्मित फिलामेंट यार्न को छोड़कर) में उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई. वस्त्र का उत्पादन भी मिल सेक्टर को छोड़कर सभी श्रेणियों में वर्ष के दौरान बढ़ा है.

सिंथेटिक सेगमेंट पर कपास की घटती कीमतों का प्रभाव

अधिकांश मानव निर्मित फिलामेंट तथा फाइबर की मांग 2014-15 में मंद रही. यह वर्ष के दौरान कॉटन यार्न की कीमतों में गिरावट के कारण था इसके अलावा, जुलाई 2014 में परिष्कृत टेरीफथैलिक ऐसिड, (एक प्रमुख निविष्टि) के आयात पर एंटी डम्पिंग शुल्क लगाने से पालिएस्टर के आयात में वृद्धि हुई. इससे पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का देशी उत्पादन और प्रभावित हुआ.

2014-15 में सिंथेटिक फैब्रिक की मांग भी कॉटन फैब्रिक की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि के कारण स्थिर हो गई है. कॉटन की कीमतों में गिरावट के कारण देशी परिधान विनिर्माताओं ने सिंथेटिक से बने फैब्रिक की तुलना में कॉटन से बने फैब्रिक को तरजीह दी.

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

भारत टेक्सटाइल तथा वस्त्रों (एचएस कोड : 50 से 63) का निवल निर्यातक है. 2014-15 में इसका निर्यात 37.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा और आयात 6.0 बिलियन यूएस डॉलर रहा. भारत द्वारा टेक्सटाइल और वस्त्र का निर्यात गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में 0.5 प्रतिशत की धीमी गति से बढ़ा.

यूएसए भारत के टेक्सटाइल एवं वस्त्र निर्यात के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य स्थान है. 2014-15 में कुल निर्यात में इसका 19.0 प्रतिशत हिस्सा रहा. इसके बाद यूएई (10.0 प्रतिशत), चीन (6.9 प्रतिशत), यूके (6.6 प्रतिशत) तथा बांग्लादेश (5.2 प्रतिशत) का स्थान रहा. दूसरी ओर, चीन टेक्सटाइल तथा वस्त्र खंड में भारत के आयात में अधिकांश हिस्सा रखता है (2014-15 में 43.6 प्रतिशत).

भावी संभावनाएं

- **यार्न :** वर्ष के दौरान एकीकृत परिधान एवं फैब्रिक निर्माताओं द्वारा यार्न की खरीद में वृद्धि की बदौलत देशी बाजार में यार्न की मांग में 2015-16 में तेजी रहने की संभावना है.
    - चीन, जहां विश्व में सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है, से कॉटन यार्न की मांग में पुन: बहाली के चलते यार्न के लिए निर्यात मांग में 2015-16 में सुधार होने का अनुमान है. भारतीय बाजारों में कॉटन यार्न की कीमतों में गिरावट का अनुमान है. परिणामस्वरूप, चीनी टेक्सटाइल मिलों द्वारा भारत से यार्न की खरीद बढ़ाने की संभावना है. इसके अलावा, बांग्लादेश और वियतनाम द्वारा भी अपने बढ़ते उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से यार्न की खरीद बढ़ाने की उम्मीद की जाती है.
- **फैब्रिक :** फैब्रिक निर्माताओं द्वारा 2015-16 में अपना उत्पादन बढ़ाने की आशा की जाती है. इसे रेडीमेड वस्त्रों, होम टेक्सटाइल तथा तकनीकी टेक्सटाइल्स के निर्माताओं द्वारा फैब्रिक की खरीद में अच्छी वृद्धि द्वारा समर्थन मिलने की संभावना है. वर्ष के दौरान, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में खुदरा पहुंच में वृद्धि, उच्च प्रयोज्य आय तथा जीवन-शैली में सुधार जैसे कारकों से फैब्रिक तथा परिधान की देशी खपत को बढ़ावा मिलने की संभावना है. परिधान के लिए विदेशी मांग चालू राजकोषीय वर्ष में अच्छी रहने की उम्मीद है. वस्त्र उद्योग में भारी निवेश से भी कुल फैब्रिक उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है.
    - सिंथेटिक फिलामेंट तथा फाइबर जैसे पॉलिएस्टर आदि की कीमतें गिर रही हैं और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते कीमतें कम रहने की उम्मीद है. फलस्वरूप, चालू वितीय वर्ष में परिधान निर्माताओं द्वारा सिंथेटिक से बने फैब्रिक की मांग बढ़ने की उम्मीद है.
- **वस्त्र :** यूएस तथा ईयू में आर्थिक कार्यकलापों से 2015-16 के दौरान सुधार होने का अनुमान है. फलस्वरूप, भारतीय परिधान निर्यातकों को चालू वित्त वर्ष में यूएस तथा ईयू से बड़े निर्यात ऑर्डर मिलना जारी रहेगा.
    - इसके अलावा, चीन में श्रम लागतों में वृद्धि से इसका परिधान निर्यात अन्य निर्यातक देशों की तुलना में महंगा होने की संभावना है. फलस्वरूप, वर्ष के दौरान चीन का निर्यात कमजोर रहने की संभावना है क्योंकि क्रेता वैकल्पिक सोर्सिंग स्थानों की तलाश में रहेंगे. इससे चीन के खोते बाजार हिस्से को हथियाने के लिए भारत को एक सुनहरा अवसर मिलने की संभावना है.

भारतीय एक्ज़िम बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने लघु एवं मझौले उद्यमों पर विशेष बल के साथ प्रभावी बाजार प्रवेश व्यवस्था के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर दिया है. एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातक समुदाय को जोखिम मुक्त, दायित्वरहित निर्यात वित्तपोषण विकल्प प्रदान करती हैं जिससे उन्हें नये बाजारों में प्रवेश करने और विदेशों में मौजूदा बाजारों में अपनी निर्यात मात्रा को बढ़ाने में सहायता मिलती है.

एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थाओं, क्षेत्रीय विकास बैंकों, सरकारी और अन्य विदेशी संस्थाओं को ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है. ये ऋण-व्यवस्थाएं उन देशों के क्रेताओं को भारत से आस्थगित भुगतान शर्तों पर विकासपरक तथा बुनियादी संरचना, परियोजना, उपकरण, माल एवं सेवाओं का आयात करने में समर्थ बनाती हैं.

एक्ज़िम बैंक भारत सरकार के आदेश पर भी ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करता है. भारत सरकार के आदेश पर जारी ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक माल की शिपिंग पर भारतीय निर्यातकों को संविदा मूल्य के 100 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अपफ्रंट करता है, बशर्ते कि संविदा मूल्य का कम से कम 75 प्रतिशत माल एवं सेवा भारत से लिया जाए.

ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत को उभरते बाजारों में परियोजना निष्पादन क्षमताओं को प्रदर्शित करने में भी समर्थ बनाया है. ऋण- व्यवस्थाओं ने हाल के वर्षों में विशेषकर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा सीआईएस देशों में पर्याप्त पहुँच बनाने में सहायता प्रदान की हैं. बैंक की वर्तमान में 198 ऋण-व्यवस्थाएं परिचालन में हैं जिनके अंतर्गत अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, यूरोप तथा सीआईएस के 63 देशों में 12.16 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की ऋण- व्यवस्थाएं भारत से निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं. इस प्रकार ऋण- व्यवस्थाएं भारत से विकासशील देशों को परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में कार्य करती हैं.

एक्ज़िम बैंक ने भारत सरकार के आदेश और सहयोग से अप्रैल-जून 2015 तिमाही के दौरान निम्नलिखित चार ऋण-व्यवस्थाओं पर हस्ताक्षर किए हैं :

- कांगो गणराज्य सरकार को बांदुन्दु प्रदेश में बिजली वितरण परियोजना के विकास हेतु 34.50 मिलियन यू एस डॉलर तथा कांगो गणराज्य के कासैई प्रांत में केटेन्डे जल विद्युत पॉवर परियोजना (ट्रांसमिशन एवं वितरण) हेतु 109.942 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्थाएं. कुल 144.4 मिलियन यूएस डॉलर की उपर्युक्त दो ऋण-व्यवस्थाओं सहित एक्ज़िम बैंक द्वारा भारत सरकार के आदेश पर कांगो गणराज्य को अब तक कुल 494.94 मिलियन यू एस डॉलर की सात ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं. कांगो गणराज्य सरकार को इससे पहले दी गई ऋण-व्यवस्थाएं सीमेंट प्लांट की स्थापना, हैंड पम्प, सबमर्सिबल पंप स्थापित करने और हाइड्रोपॉवर परियोजना के निष्पादन के लिए प्रदान की गई थीं.
- तंजानिया सरकार को तंजानिया में टबोरा, आईगुंगा तथा ज़ेगा तक लेक विक्टोरिया पाइपलाईन के विस्तार के वित्तपोषण हेतु 268.35 मिलियन यू एस डॉलर की ऋण-व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक इससे पहले भी तंजानिया को ट्रैक्टरों, पम्पों तथा उपकरणों की आपूर्ति सहित जल आपूर्ति योजनाओं के वित्तपोषण के लिए कुल 254.69 मिलियन यूएस डॉलर राशि की तीन ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कर चुका है.
- म्यॉमा फॉरेन ट्रेड बैंक (एमएफटीबी) को म्यांमार में रि-मिनदत मार्ग पर माइक्रोवेव रेडियो लिंक के कार्यान्वियन के वित्तपोषण के लिए 6.20 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण-व्यवस्था. एक्ज़िम बैंक द्वारा म्यांमार में रेलवे परियोजनाओं, रिफाइनरी परियोजनाओं, वाहनों की असेम्बली / निर्माण संयंत्र, सिंचाई योजनाओं, ट्रांसमिशन लाइनों, पेट्रो-रसायन कॉम्प्लेक्स के उन्नयन के लिए एमएफटीबी को इससे पहले भी 607.59 मिलियन यूएस डॉलर की दस ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा चुकी हैं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

नदीम पंजेतन
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
फोन - (022) 22172310
फैक्स - (022) 22182460
ईमेल : eximloc@eximbankindia.in

ग्रीस को निर्यात : भारत पर संकट का मामूली प्रभाव

नई दिल्ली : सरकार ने कहा है कि भारत के निर्यात में ग्रीस का हिस्सा लगभग 0.1 प्रतिशत है. अत: वित्तीय संकट के कारण इस पर प्रभाव मामूली होगा. राज्य सभा को एक लिखित उत्तर में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कहा, "भारत से ग्रीस को निर्यात का हिस्सा सिर्फ लगभग 0.1 प्रतिशत है, अतएव ग्रीस में आर्थिक संकट के कारण भारतीय निर्यात पर सीधा प्रभाव मामूली रहने की संभावना है." तथापि सरकार विभिन्न देशों को विभिन्न क्षेत्रों के निर्यात प्रदर्शन की लगातार निगरानी कर रही है और वैश्विक वित्तीय स्थिति तथा समग्र आर्थिक निहितार्थ को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यकता आधारित उपाय करती है.

सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन परिषद् की स्थापना

नई दिल्ली : छमाही अवधि के दौरान निर्यात में निरंतर गिरावट को देखते हुए भारत सरकार ने केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की है जिसमें राज्यों के व्यापार तथा वाणिज्य मंत्री और अन्य अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे. इसके अलावा, वाणिज्य, राजस्व, नौवहन, नागरिक उड्डयन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण तथा आर्थिक मामलों के सचिवों सहित 14 केन्द्रीय सचिव भी परिषद् के सदस्य होंगे. व्यापार विकास तथा संवर्धन परिषद की अधिसूचना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जुलाई 2015 में जारी की गई. अधिसूचना में उल्लिखित है, "राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समर्थकारी वातावरण उपलब्ध कराने हेतु उपायों पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर वार्ता सुनिश्चित करने और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने में राज्यों को सक्रिय भागीदार बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से व्यापार विकास तथा संवर्धन परिषद् का गठन करने का निर्णय लिया गया है." इसका लक्ष्य 2019-20 तक 900 बिलियन यूएस डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल करना है. परिषद् राज्यों को राष्ट्रीय नीति के अनुरूप निर्यात रणनीतियां विकसित तथा कार्यान्वित करने में उनकी मदद करेगी तथा व्यापार नीति पर अपना परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी. इसके साथ ही परिषद भारत की व्यापार संभाव्यता तथा अवसरों को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय घटना-क्रमों से उन्हें अवगत कराएगी और स्थिति से निपटने के लिए उन्हें तैयार करेगी.

भारत से औषध निर्यात - ट्रैकिंग चिप्स का प्रयोग

नई दिल्ली : एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने सभी भारतीय औषध निर्यातक फर्मों पर निगरानी रखने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है. तदनुसार अक्तूबर से कंपनियां पैकेजिंग के विभिन्न स्तरों पर निर्धारित विनिर्माण डेटा का अनुपालन करेंगी. वाणिज्य मंत्रालय ने इसके लिए अगले दो महीने के भीतर प्रौद्योगिकियों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है. औषध उद्योग अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकियों तथा दिशानिर्देशों पर स्पष्टता की प्रतीक्षा में है. औषध विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है, ''हम देशी निर्माताओं पर एक डाटाबेस तैयार करने की योजना बना रहे हैं जो विश्व भर में विनियामकों तथा रिटेलरों के लिए खुला रहेगा." "अब वैश्विक आयातक ऑनलाइन अपने पारेषण की स्थिति देख सकेंगे और विनिर्माण के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये कदमों की जांच कर सकेंगे."

इस प्रक्रिया में भारतीय औषध निर्माताओं को अपने निर्यात को ट्रैंक करने और यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि उनके शिपमेंट के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है. भारत बार-कोड सिस्टम को कार्यान्वित करने वाला पहला देश है. सरकार ने देश से बाहर भेजे जाने वाले औषधों के सभी कार्टूनों की बार-कोडिंग अनिवार्य कर दी है. इसकी शुरूआत जून से हुई है. सरकार को इस बात की चिंता है कि गुणवत्ता संबंधी शिकायतें ब्रांड इंडिया की छवि को धूमिल कर रही हैं. औषध निर्माताओं ने उत्पादों के परिवहन के समय वैश्विक स्वास्थ्य विनियामकों के निष्कर्षों पर कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं.

मई में श्री लंका को ऑटोमोबाइल निर्यात में चार गुना उछाल

नई दिल्ली : इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् (ईईपीसी) ने कहा है कि श्री लंका को ऑटोमोबाइल का निर्यात पिछले वर्ष मई महीने में 14.6 मिलियन यूएस डॉलर से इस वर्ष मई में लगभग चार गुना बढ़कर 56.5 मिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है. ईईपीसी ने यह भी कहा है कि यूएई ने ऑटो निर्यात की गति को बनाये रखने में सहायता की है. जिसका शिपमेंट 10.2 प्रतिशत बढ़कर मई में 18.6 मिलियन यूएस डॉलर हो गया. इटली ने समीक्षाधीन महीने के दौरान 14.8 मिलियन यूएस डॉलर के स्तर पर निर्यात में 37.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि स्पेन को निर्यात 10.2 प्रतिशत बढ़कर 17.5 मिलियन यूएस डॉलर हो गया.

इसके विपरीत, भारत के प्रमुख आटोमोबाइल निर्यात गंतव्य स्थान मेक्सिको ने 47.8 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य के निर्यात पर 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है. इसी प्रकार, यूके को शिपमेंट में भी 32 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आयी है. अल्जीरिया ने भी 21.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है. ईईपीसी का कहना है, "कुल मिलाकर ऑटोमोबाइल निर्यात पिछले वर्ष मई महीने के 526 मिलियन यूएस डॉलर से 2.7 प्रतिशत घटकर इस वर्ष के मई महीने में 512 मिलियन यूएस डॉलर रहा." पैसेंजर कार का निर्यात यूरोप तथा अल्जीरिया जैसे पारंपरिक बाजारों में चुनौतियों के कारण 2014-15 में 1.7 प्रतिशत घटकर 5,42,082 यूनिट रहा.

एक्ज़िम बैंक ने ग्रीन बांड के जरिए 500 मिलियन यूएस डॉलर की राशि जुटायी

मुंबई : एक्ज़िम बैंक ने 24 मार्च, 2015 को 500 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य के 5 वर्षीय रेग एस ग्रीन बाँड जारी किए. जोरदार मांग के चलते 140 से अधिक खातों से निर्गम को लगभग 3.2 गुना अधिक अभिदान प्राप्त हुआ.

500 मिलियन यू एस डॉलर राशि के इस 5 वर्षीय यूरो डॉलर ग्रीन बाँड निर्गम को 2.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की फिक्स्ड कूपन दर पर जारी किया गया जो यू एस ट्रेजरी (यू एस टी) दर से 147.50 आधार बिन्दु ऊपर है. बांड निर्गम की यह दर न केवल सेकंडरी बाज़ार में समान बांडों की वर्तमान दर से प्रतिस्पर्द्धी दर है बल्कि फरवरी 2015 में इससे पूर्व जारी किए गए बैंक के 5.5 वर्षीय 500 मिलियन यू एस डॉलर के रेग एस बॉड की कूपन दर से भी कम है.

यह ट्रांजेक्शन भारत से बाहर जारी किया गया पहला यू एस डॉलर मूल्यांकित ग्रीन बांड होने के साथ-साथ एशिया में 2015 में जारी किया गया पहला बेंचमार्क-आकार का ग्रीन बांड तथा एशिया के बाहर जारी किया गया तीसरा ग्रीन बॉड है. इससे एक्ज़िम बैंक को अपने निवेशक आधार को व्यापक बनाने तथा ऐसे बाजार में पहुँच बनाने में मदद मिली है जहां निवेशक सामाजिक उत्तरदायित्व वाली परियोजनाओं या निवेश विकल्पों में निवेश करना पसंद करते हैं. एक्ज़िम बैंक इसके जरिए जुटाई गई राशि का उपयोग बांग्लादेश तथा श्री लंका सहित अन्य देशों में ग्रीन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए करेगा.

इस बॉड निर्गम ने ग्रीन इन्वेस्टरों तथा रियल मनी खातों की सक्रिय सहभागिता से 140 से अधिक खातों से 1.6 बिलियन यू एस डॉलर से अधिक राशि आकर्षित की. निवेशकों में मुख्य रूप से फंड मैनेजर (58 प्रतिशत), बैंक (20 प्रतिशत), सोवेरिन वेल्थ फंड्स / बीमा कंपनियां (18 प्रतिशत) सहित अन्य प्रमुख निवेशक रहे. बॉड निर्गम की 60 प्रतिशत राशि एशियाई निवेशकों, 30 प्रतिशत राशि ई एम ई ए (यूरोप, मध्य पूर्व तथा एशियाई) निवेशकों तथा शेष ऑफशोर यू एस निवेशकों के बीच आबंटित की गई. बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल्ल लिंच तथा जे.पी. मोरगन इस बॉड पेशकश के लिए संयुक्त रूप से लीड मैनेजर थे. भारतीय एक्ज़िम बैंक को स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा 'बी बी बी-' तथा मूडीज द्वारा 'बी ए ए3 की रेटिंग प्राप्त है, जो कि भारत सरकार की रेटिंग के समतुल्य है.

एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर ने कहा कि "ग्रीन बांड जारी करना पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है. साथ ही इसने पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की मदद करने संबंधी हमारे प्रयासों के लिए पर्यावरण संवेदी निवेशकों से जुड़ने में हमारी मदद की है.

एक्ज़िम बैंक पूंजी जुटाने हेतु अन्य भारतीय जारीकर्ताओं के लिए नए बाजारों को खोलने में अग्रणी रहा है. एक्ज़िम बैंक उरीदाशी, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, सिंगापुर डॉलर तथा समुराई बाँड बाजार से पूंजी जुटाने वाला पहला बैंक रहा है उसके बाद ही अन्य भारतीय कंपनियों ने इस बाजार में अपनी पहुँच बनाई. अन्य भारतीय जारीकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बाजार खोलने का यह एक अन्य प्रयास है और हमें उम्मीद है कि भारतीय कंपनियां इस महत्वपूर्ण ग्रीन बॉड बाजार में अपनी पहुंच बनाएगी."

पुणे में परियोजना निर्यात पर गोलमेज चर्चा

पुणे: एक्ज़िम बैंक ने विनिर्माण निर्यात तथा भारत में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजना निर्यातों में प्रभावी वृद्धि के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु 26 जून, 2015 को पुणे में 'परियोजना निर्यात पर गोलमेज चर्चा' का आयोजन किया.

परियोजना निर्यात किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होते हैं. एक्ज़िम बैंक परियोजना निर्यातों, जिनमें विदेशी औद्योगिक टर्नकी परियोजनाएं, सिविल निर्माण संविदाएं, आपूर्ति संविदाएं तथा तकनीकी एवं सलाहकारी सेवा संविदाएं शामिल हैं, के संवर्द्धन के लिए समन्वयक एवं सुगमकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

एक्ज़िम बैंक के ऋण-व्यवस्था एवं क्रेता ऋण जैसे प्रमुख कार्यक्रम विदेशी क्रेताओं को निधिक विकल्प उपलब्ध कराते हैं ताकि भारतीय परियोजना निर्यातक विकासशील देशों में नए बाजारों में पहुंचकर भारत से माल एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन में सहायता कर सकें.

एक्ज़िम बैंक द्वारा 81 देशों में 139 भारतीय कंपनियों द्वारा निष्पादित की जा रही 189,736 करोड़ रुपये (लगभग 30.45 मिलियन यू एस डॉलर) मूल्य की 441 परियोजना निर्यात संविदाओं को सहायता प्रदान की गई है. एक्ज़िम बैंक द्वारा इन परियोजनाओं को निधिक एवं गैर-निधिक दोनों प्रकार की सहायता प्रदान की गई है.

सेमिनार को एक्ज़िम बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री डेविड रस्कीना द्वारा संबोधित किया गया तथा एक पैनल चर्चा भी की गई. श्री मलय दास, संयुक्त प्रबंध निदेशक, थिसेनक्रुप इंडस्ट्रीज प्रा. लि.; श्री अमिताभ मुखोपाध्याय, सी एफ ओ एवं कार्यकारी उपाध्यक्ष, थर्मेक्स लि.; श्री सुब्रत मिश्रा, वरिष्ठ लीडरशिप एवं सी एफ ओ, जॉन डीरे; श्री सुरेश कुमार, कार्यकारी उपाध्यक्ष अफ्रीका, इंटरनेशनल प्रोजक्ट्स, प्राज इंडस्ट्रीज लि.; तथा श्री डी.टी. अर्जुन, उपाध्यक्ष एवं प्रमुख - सीमेंट डिविजन, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लि. ने भारतीय परियोजना निर्यातकों के समक्ष "चुनौतियां एवं आगे की राह" पर चर्चा की तथा भारतीय परियोजना निर्यातकों को समान अवसर कैसे प्रदान किए जाएं, को सुनिश्चित करने पर अपने-अपने विचार रखे. इस सेमिनार में 50 से अधिक अग्रणी भारतीय कंपनियों के लगभग 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया.

भारतीय औषधि उद्योग ने देश में बढ़ते उपभोग स्तरों और निर्यात बाजारों से जोरदार मांग की बदौलत हालिया वर्षों में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है. उद्योग ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, टेक्नोलॉजी आधार और उत्पादों की विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रगति की है. सस्ती औषधियों का उत्पादन करने की भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों की क्षमता के चलते निर्यात बाजार से मांग निरंतर बढ़ रही है.

भारतीय औषधि उद्योग

भारतीय औषधि उद्योग विश्व में मात्रा की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य की दृष्टि से दसवां सबसे बड़ा (वैश्विक हिस्सा 2.5 प्रतिशत) स्थान रखता है. भारतीय औषधि उद्योग का आकार 2013-14 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान मोटे तौर पर 13 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ा है.

यह उद्योग वैश्विक मंदी से अधिक प्रभावित नहीं हुआ है. उद्योग का निर्यात 2009-10 के दौरान 8.7 बिलियन यूएस डॉलर से 2010-11 के दौरान 18.5 प्रतिशत की दर से बढ़कर 10.3 बिलियन यूएस डॉलर और 2012-13 में 25.1 प्रतिशत बढ़कर 12.9 बिलियन यूएस डॉलर हो गया. तथापि, हालिया वर्षों में, हालांकि निरपेक्ष मूल्य की दृष्टि से निर्यात में वृद्धि हुई है किन्तु वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि मुख्यत: रुपये में कमजोरी के कारण यूएस डॉलर मूल्य की दृष्टि से गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाती है **(चार्ट)**.

यूएसए (30.9 प्रतिशत हिस्से के साथ), रूस (4.8 प्रतिशत), दक्षिण अफ्रीका (4.5 प्रतिशत), यूके (3.6 प्रतिशत) और नाइजीरिया (3 प्रतिशत) वर्ष 2013-14 के दौरान भारत के ड्रग फार्मूलेशनों तथा जैविक उत्पादों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थान रहे. तथापि 2013-14 के दौरान, नीदरलैंड, जिसे यूरोपीय संघ के लिए प्रवेशद्वार बाजार माना जाता है, भारतीय फार्मूलेशनों तथा जैविक उत्पादों के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरा है. यूएसए (14.2 प्रतिशत), जर्मनी (5.3 प्रतिशत), ब्राजील (4.5 प्रतिशत), यूके (3.7 प्रतिशत) और जापान 3.5 प्रतिशत) 2013-14 में भारत के थोक और मध्यवर्ती औषधि के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थान रहे.

चार्ट : भारत से औषधि उत्पादों का निर्यात

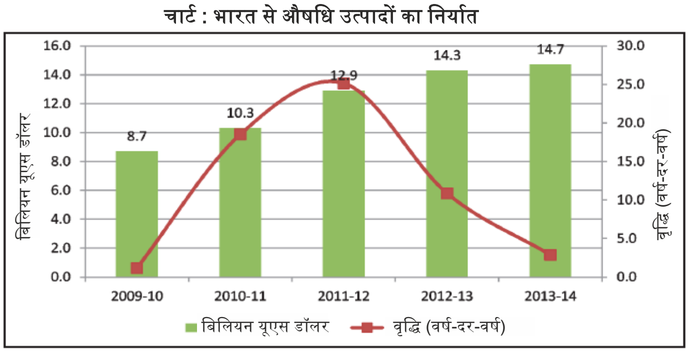

डीजीसीआईएस द्वारा एचएस कोड के बल्क ड्रग तथा ड्रग मध्यवर्ती और ड्रग फार्मूलेशन तथा जैविक रूप में वर्गीकरण पर आधारित विश्लेषण.
स्रोत – डीजीसीआईएस (डाटा स्रोत)- एक्ज़िम बैंक विश्लेषण

भारत से फार्मास्युटिकल्स के कुल निर्यात में फॉर्मूलेशनों का हिस्सा (75 प्रतिशत) थोक औषधि के हिस्से (25 प्रतिशत) से अधिक है.

प्रमुख उद्योग प्रवृत्तियां

भारत से फॉर्मूलेशनों तथा थोक औषधि का निर्यात 2013-14 तक 5 वर्ष की अवधि के दौरान डॉलर मूल्य की दृष्टि से लगभग 17 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ा है. अर्ध विनियमित बाजारों को निर्यात में वृद्धि 2013-14 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 12 प्रतिशत पर बनी रही, जबकि विनियमित बाजारों को निर्यात पिछले वर्ष में 18 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस अवधि में 10 प्रतिशत की सामान्य दर से बढ़ा. यह मंदी यूएसएफडीए द्वारा भारतीय कंपनियों से आयात अलर्ट्स के कारण आयी. अर्ध-विनियमित बाजारों में वृद्धि मुख्यत: एशिया तथा अफ्रीका द्वारा संचालित रही है.

थोक औषधि का निर्यात 2008-09 से 2013-14 के बीच लगभग 17 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है. यह वृद्धि मुख्यत: उच्च कोटि के एपीआई के लिए पसन्दीदा विनिर्माण केन्द्र के रूप में भारत के उभार के कारण हुई है. यूएस एफडीए के पास फाइल की गई कुल ड्रग मास्टर फाइलिंग्स में, भारत का हिस्सा 2001 के लगभग 19 प्रतिशत से बढ़कर जून 2014 को समाप्त छमाही मे लगभग 52 प्रतिशत हो गया है.

विलय एवं अधिग्रहण - वर्ष 2013 के दौरान भारतीय औषधि उद्योग ने फॉर्मा तथा बायोटेक सेक्टर (आवक, जावक तथा देशी) में कुल 30 विलय एवं अधिग्रहण सौदे किए जितक कुल मूल्य 2012 के 1.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2013 में 2.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा.

पेटेंट – भारतीय पेटेंट कार्यालय के अनुसार, 2012-13 के दौरान, कुल 43,674 पेटेंट फाइल किए गए, जिसमें से सिर्फ 6.8 प्रतिशत पेटेंट ड्रग्स एवं फार्मास्युटिकल्स सेक्टर में फाइल किए गए; और वर्ष में मंजूर किए गए कुल 4126 पेटेंट में से लगभग 8.3 प्रतिशत हिस्सा फार्मास्युटिकल्स के लिए था.

आर एंड डी - भारतीय फार्मास्युटिकल्स कंपनियों ने अपने आर एंड डी बजट में भारी वृद्धि की है. 2013-14 के दौरान अग्रणी भारतीय फार्मा कंपनियों ने आरएंडडी पर 5 बिलियन रुपये से 12 बिलियन रुपये के बीच राशि खर्च की जो पूर्ण रूप में तथा निवल राजस्व के अनुपात के रूप में वृद्धि दर्शाता है.

भावी संभावनाएं

उद्योग में 2020 तक 11-13 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. यूएस से उभरते विशाल जिनेरिक ड्रग्स अवसर को देखते हुए भारत समग्र एएनडीए अनुमोदनों में कुल अनुमोदनों का 38 प्रतिशत का उच्च हिस्सा रखता है जो यूएस के बाद दूसरा है. 2020 तक जिनेरिक्स के वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 20 प्रतिशत होने का अनुमान है. यूएसए में पंजीकृत कुल ड्रग मास्टर फाइलिंग्स में 48 प्रतिशत हिस्से के साथ भारतीय औषधि उद्योग द्वारा 2020 तक 45 बिलियन यूएस डॉलर का राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद है. वैश्विक फॉर्मास्युटिकल आयात में लगभग 8 प्रतिशत हिस्से के साथ, अर्ध-विनियमित बाजार - विशेषकर उभरते बाजार : ब्राजील, रूस, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स भारतीय औषधि उद्योग के लिए संभाव्य बाजार हो सकते हैं.

1 अप्रैल, 2015 को घोषित विदेश व्यापार नीति (एफ टी पी) 2015-2020 में विदेश व्यापार, व्यापार सुगमीकरण तथा भारत में कारोबार करने की सहूलित को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय लागू किए गए हैं.

इस वार्षिक अनुपूरक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

- दो नई योजनाओं की घोषणा – भारत से पण्य निर्यात योजना (एमईआईएस) तथा भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस).
- एमईआईएस में अधिसूचित बाजारों (3 समूहों में वर्गीकृत अर्थात देश समूह ए, बी तथा सी) को अधिसूचित माल के निर्यात को एफओबी मूल्य के प्रतिशत के रूप में मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जा सकता है. इसमें पांच योजनाओं अर्थात् फोकस उत्पाद योजना, बाजार सम्बद्ध फोकस उत्पाद योजना, फोकस बाजार योजना, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोत्साहन स्क्रिप तथा वीकेजीयूवाई का विलय कर दिया गया है.
- एसईआईएस पहले 'भारतीय सेवा प्रदाताओं' के लिए उपलब्ध सर्व्ड फॉर्म इंडिया स्कीम के विपरीत 'भारत में स्थित सेवा प्रदाताओं' के लिए उपलब्ध है और निर्दिष्ट सेवाओं के निर्यात के लिए एसईआईएस रिवॉर्ड दरें अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पर आधारित होंगी. ड्यूटी स्क्रिप जारी करने के प्रयोजनार्थ इसमें प्रोफेशनल सेवाओं, अन्य कारोबारी सेवाओं, निर्माण तथा सम्बद्ध इंजीनियरिंग सेवाओं, पर्यटन तथा यात्रा, परिवहन के सभी माध्यमों की अनुषंगी सेवाओं को शामिल किया गया है.
- विदेश व्यापार नीति 2015-2020 में अधिसूचित बाजारों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है – पारंपरिक बाजारों (30) के लिए श्रेणी ए; यूरोपीय संघ (28), यूएसए तथा कनाडा; उभरते एवं फोकस बाजारों (139) के लिए श्रेणी बी: अफ्रीका (56), लैटिन अमेरिका तथा मेक्सिको (45), सीआईएस देश (12), तुर्की तथा पश्चिम एशियाई देश (13), आसियान देश (10), जापान, दक्षिण कोरिया, चीन , ताइवान; तथा अन्य बाजारों (70) के लिए श्रेणी सी.
- एमईआईएस तथा एसईआईएस के अंतर्गत जारी सभी स्क्रिप्स तथा इन स्क्रिपों पर आयातित माल पूर्णत: हस्तांतरणीय और सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क तथा सेवा कर के भुगतान के लिए प्रयोज्य होंगे.
- एमईआईएस तथा एसईआईएस प्रोत्साहन योजनाएं अब एसईजेड में स्थित इकाइयों के लिए भी लागू होंगी.
- उच्च देशी तत्व और भारत में अधिक मूल्य योजन वाले उत्पादों के लिए एमईआईएस के अंतर्गत उच्चतर प्रोत्साहन होंगें.
- वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की सहभागिता बढ़ाने के लिए एफटीपी 2015-2020 ने इस योजना के अंतर्गत मध्यवर्ती माल की 1725 लाइनों (जिनका इस्तेमाल अन्य देशों के विनिर्माण में निविष्टियों के रूप में किया जाता है और जो पश्च विनिर्माण सहबद्धताओं को मजबूत करेंगी); पूंजीगत माल क्षेत्र की 1109 लाइनों (विनिर्माण आधार को मजबूत करने के लिए) और उपभोक्ता माल क्षेत्र की 1730 लाइनों (मेक इन इंडिया ब्रांड के मजबूत होने से निर्यात में तीव्र वृद्धि देने वाले क्षेत्र) की शुरुआत की है.

स्टेटस होल्डर की पहचान के लिए निर्यात कार्य-निष्पादन के मानदंड को रुपये से यूएस डॉलर अर्जन में परिवर्तित किया गया है. स्टेटस होल्डर की नामावली में भी परिवर्तन किया गया है. स्टेटस होल्डर विभिन्न विदेश व्यापार करारों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने निर्मित माल को 'भारत में निर्मित' के रूप में स्वयं प्रमाणित कर सकेंगे.'

- मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए निर्यात दायित्व को ईपीसीजी योजना के अंतर्गत देशी खरीद के अंतर्गत 90 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है. तथापि ईपीसीजी योजना के अंतर्गत आयात एंटी-डम्पिंग शुल्क तथा सुरक्षा शुल्क के भुगतान से छूट के लिए पात्र नहीं होगा.
- ट्रांजैक्शन लागतों को कम करने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं: दस्तावेजों / आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग तथा निर्यातकों / आयातकों द्वारा एफटीपी के अंतर्गत आवेदन के लिए 24 x 7 वातावरण में ऑनलाइन व्यापार; एससीओएमईटी (विशेष रसायन, ऑर्गेनिज्म, सामग्री, उपकरण तथा प्रौद्योगिकी) मदों के निर्यात अनुमोदन, मानदंड निर्धारण, आयात तथा निर्यात प्राधिकरण आदि के लिए ऑनलाइन अंतर-मंत्रिमंडलीय परामर्श; आयात तथा निर्यात के प्रयोजनार्थ प्रक्रियाओं / प्रक्रमों का सरलीकरण, डिजिटाइजेशन तथा ई-गवर्नेंस; और ई-गवर्नेंस पहल जैसे निर्यात दायित्व उन्मोचन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) ऑनलाइन जारी करना; पैन के लिए सीबीडीटी के साथ ऑनलाइन संप्रेषण, सीमाशुल्क से डीजीएफटी को प्रविष्टि पत्र (आयात ब्यौरे) भेजने के लिए ऑनलाइन संदेश का आदान-प्रदान.
- ईओयू, ईएचटीपी तथा एसटीपी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलें शुरू की गईं : ईओयू, ईएचटीपी तथा एसटीपी को आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को साझा करने की अनुमति दी गई है. निर्यातोन्मुख इकाइयों को निर्यात पोर्ट के नजदीक मालगोदाम बनाने की अनुमति दी गई है. एसटीपी/ ईएचटीपी इकाइयों के डिबांडिंग / एक्जिट को फास्ट ट्रैक करने के लिए प्रक्रिया सरलीकृत की जाएगी; और 100 मिलियन रुपये या इससे अधिक का भौतिक निर्यात टर्नओवर रखने वाली निर्यातोन्मुख इकाइयों को आयात तथा देशी खरीद की फास्ट ट्रैक मंजूरी की सुविधा प्रदान की गई है.
- अतिरिक्त पोर्टों अर्थात कालीकट एयरपोर्ट, केरल तथा एराकोनम आईसीडी, तमिलनाडु को आयात तथा निर्यात के लिए पंजीकृत पोर्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है.
- गुणवत्ता शिकायतों तथा व्यापार विवादों का समाधान करने के लिए डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों के 22 कार्यालयों में गुणवत्ता शिकायत तथा व्यापार विवाद समिति (सीक्यूसीटीडी) का गठन किया जाएगा.

एक्ज़िम बैंक के एम ए एस कार्यकलाप

अप्रैल-जून 2015

एक्ज़िम बैंक अपनी विपणन सलाहकारी सेवाओं (एमएएस) के माध्यम से भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमता तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण संवर्धनात्मक भूमिका अदा करता है. ऐसे ही एक प्रयास के रूप में बैंक ने मुंबई में आधारित एक निर्माता निर्यातक को एक दक्षिण अफ्रीकी आयातक से स्टील रिंग चेन के लिए ऑर्डर प्राप्त करने में सहायता प्रदान की. आयातक को कोलम्बिया में समुद्री पोर्ट तथा मालगोदामों में सामग्री के संचालन के प्रयोजनार्थ विभिन्न आकार के लिंक चेनों की जरूरत थी. एक्ज़िम बैंक की सहायता से ऑर्डर सफलतापूर्वक दिया गया और निर्यातक दक्षिण अफ्रीकी बाजार में विस्तार कर सका.

एक्ज़िम बैंक ने हैंडलूम टेक्सटाइल तथा एक्सेसरीज़ की बुनाई में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में उत्तराखंड की एक महिला बुनकर संघ की भी सहायता की है. यह कार्यक्रम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जून से नवंबर 2015 तक छः महीने की अवधि के लिए 20 महिला बुनकरों के लिए आयोजित किया जा रहा है. 2013 में केदारनाथ घाटी में विनाशकारी बाढ़ से कई लोग बेघर तथा आय-रहित हो गए. महिला बुनकर संघ लगभग 300 महिलाओं को आजीविका प्रदान करता है. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं तथा उपेक्षित समुदायों, जिनकी आय का कोई अन्य वैकल्पिक स्रोत नहीं है, के सशक्तीकरण पर फोकस करते हुए आवश्यक कौशल विकसित करने तथा सतत् आय का स्रोत सृजित करने के लिए महिला बुनकरों का कौशल बढ़ाना है.

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :
सुश्री दीपाली अग्रवाल
महाप्रबंधक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक मुंबई
फोन : (022) 22172829
ईमेल : mas@eximbankindia.in

एक्ज़िमिअस प्रशिक्षण केन्द्र (ईसीएल) कार्यकलाप

अप्रैल-जून 2015

ईसीएल ने इस अवधि के दौरान निर्यातकों के लिए चार सेमिनार आयोजित किए. ईसीएल ने भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य परिमंडल के साथ मिलकर दिल्ली और अहमदाबाद में क्रमशः 17 अप्रैल 2015 और 5 जून 2015 को 'ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम' पर दो सेमिनार आयोजित किए.

एमएसएमई क्षेत्र के लिए, एसीएल ने एफआईईओ के साथ मिलकर नोएडा में 23 जून 2015 को 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना' विषय पर सेमिनार का आयोजन किया.

इसके अलावा, जम्मू एवं कश्मीर के निर्यातकों तथा उद्यमियों को वैश्विक बाजार की गतिविधियों से अवगत कराने के लिए एक्ज़िम बैंक ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से 21 मई, 2015 को श्रीनगर में 'विदेश व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता' पर एक सेमिनार आयोजित किया.

आगामी कार्यक्रम :

- विश्व व्यापार केन्द्र के साथ मिलकर 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण' पर सेमिनार
- भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ के साथ मिलकर 'भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा' पर सेमिनार
- कर्नाटक वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ के साथ मिलकर 'विदेश व्यापार में अवसर' पर सेमिनार
- लखनऊ, वाराणसी, कोलकाता तथा शिलांग में भारतीय निर्यातकों के लिए जून-सितंबर 2015 के दौरान कई निर्यात संवर्धन सेमिनार आयोजित किए जाएंगे.

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :
सुश्री दया चन्द्रहास
महाप्रबंधक
एक्ज़िमिअस शिक्षण केन्द्र एवं राजभाषा
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, मुंबई
फोन : (022)22861570 / 22830793
ईमेल:
dayachandrahas@eximbankindia.in

पुस्तक समीक्षा

'लैटिन अमेरिका, कैरेबियन एवं भारत: वादे एवं चुनौतियाँ'

लेखक - राजदूत दीपक भोजवानी

दीपक भोजवानी की पुस्तक भारत तथा लैक क्षेत्र के बीच मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के मूल मुद्दे पर फोकस करते हुए लैक क्षेत्र में प्रत्यक्षत: एक जैसे लेकिन अत्यंत विविध तैंतीस देशों राज्यों से भारतीय पाठकों को परिचित कराते हुए लैक क्षेत्र का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करती है.

नौ अध्यायों में से पहले चार अध्याय लैक क्षेत्र के इतिहास के सारगर्भित वृतांत के साथ परिदृश्य, समसामयिक परिदृश्य, क्षेत्रीय एकता से संबंधित प्रयास और वैश्विक अनुबंधों पर प्रकाश डालते हैं; और अंतिम पांच अध्याय क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों, जो भारतीय कूटनीतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अनुबंधों की बाह्य परिरेखा पर हैं, पर चर्चा करते हैं.

पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रीय फोरमों के साथ समग्र वार्ता की दिशा में भारत के प्रयास छुट-पुट तथा अप्रभावी रहे जिसका दोष दोनों पक्षों पर है. लेखक के अनुसार, निर्यात समूह में विविधता के अभाव सहित उच्च परिवहन लागत तथा कमजोर विनिर्माण आधार प्रमुख कारण रहे हैं जिनके चलते भारत के साथ लैक क्षेत्र का व्यापार भी अपेक्षाकृत निम्न स्तरों पर रहा. भोजवानी ने यह भी कहा है कि अफ्रीका के विपरीत इस क्षेत्र को इसके साथ ही तकनीकी सहायता, ऋण व्यवस्था और सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों के संबंध में भारतीय प्रशासन सुस्त रहा है. इसके साथ ही इस क्षेत्र के संबंध में भागीदारों अवसरों की अपर्याप्त राजनीतिक स्वीकृति भी रही है.

दूसरी ओर, चीन इन देशों में आक्रामक आर्थिक तथा राजनीतिक अभियान की बदौलत यूरोपीय संघ को पछाड़ते हुए लैक के दूसरे सबसे बड़े आर्थिक भागीदार के रूप में उभर रहा है.

संस्थागत व्यवस्थाओं में सुधार और विश्व के इस उभरते आर्थिक क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिए गहन और समन्वित प्रयास की जरूरत है.

पनामा

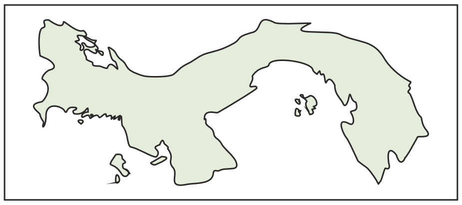

पनामा की अर्थव्यवस्था अत्यधिक विकसित सेवा क्षेत्र पर केन्द्रित है जिसका सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 75 प्रतिशत से अधिक योगदान है. पनामा का जीडीपी जनवरी-मार्च वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.9 प्रतिशत बढ़ा जो 2010-2013 में दर्ज लगभग दो अंकों के औसत से कम है. यह इस क्षेत्र में अब भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है. पनामा के कार्य-निष्पादन में मंदी धीमी वृद्धि की ओर झुकाव सूचित करती है क्योंकि कई पूंजीगत इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और निजी पोर्ट प्रणाली में निवेश की गति धीमी हो गयी है. पनामा की वृद्धि सेवा क्षेत्र और मुख्यत: परिवहन, रिटेल तथा वित्त द्वारा संचालित होने का अनुमान है. पनामा नहर वैश्विक व्यापार के लिए अनिवार्य है. सेवा अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं : कोलोन मुक्त व्यापार क्षेत्र (सीएफजेड), जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मुक्त पोर्ट है तथा ट्रान्स – पनामा पाइपलाइन, जिससे प्रशांत तथा अटलांटिक तटों के बीच कच्चे तेल का परिवहन होता है.

रूस

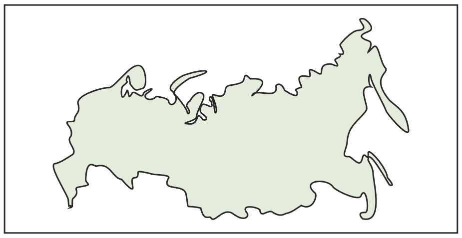

रूस की आर्थिक संभावनाएं आर्थिक प्रतिबंधों से क्षीण हुई हैं. इन प्रतिबंधों ने अंतर्निहित संरचनात्मक कमजोरियों के प्रभावों को बढ़ाया है. तेल की गिरती कीमतों और तीव्र पूंजी पलायन के चलते 2014 में रूबल का तीव्र अवमूल्यन हुआ जिससे मुद्रास्फीति बढ़ गई. 2015 में उच्च मुद्रा स्फीति और रोजगार अवसरों में कमी का प्रभाव घरेलू खपत पर पड़ने की संभावना है. कारोबारी विश्वास में कमी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और देशी गिरावट का प्रभाव निवेश पर पड़ सकता है. तथापि रूस ने ईरान तथा छ: वैश्विक शक्तियों (पी5 +1) के बीच करार का स्वागत किया है जिससे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे न बढ़ाने के प्रतिफल में देश पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए गए. कमजोर रूबल से निर्यात को बढ़ावा मिलने का अनुमान है और कमजोर देशी मांग से आयात में तीव्र गिरावट आयेगी. समग्र आर्थिक संकुचन 2009 से बहुत कम होने का अनुमान है.

रवांडा

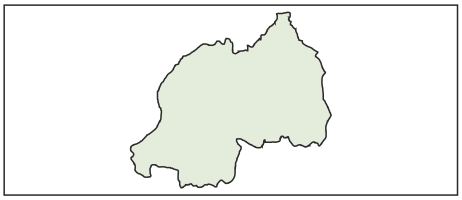

रवांडा की आर्थिक वृद्धि को कृषि क्षेत्र के जोरदार प्रदर्शन से सहायता मिलने की उम्मीद है क्योंकि कृषि क्षेत्र को मौसम संबंधी आघातों की समुत्थान-शक्ति को बढ़ावा देने, उत्पादकता बढ़ाने तथा वाणिज्यिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर निवेश से फायदा होने वाला है. लेक किवु में मेथैन गैस से बिजली उत्पादन (25 मेगावॉट), न्याबारोंगो नदी पर 28 मेगावॉट के हाइड्रोपावर प्लांट और केन्या से 30 मेगावॉट बिजली का आयात करने के लिए करार से बिजली की राष्ट्रीय आपूर्ति में काफी सुधार होगा. सरकार द्वारा – वित्तपोषित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं द्वारा समर्थित निर्माण कार्य में तीव्र विस्तार के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि होने की उम्मीद है. यद्यपि अनुदान और विदेशी सहायता में कमी औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि के लिए गिरावट का जोखिम प्रस्तुत करेगी. संचार सेवाओं को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयासों तथा परिवहन कार्यकलापों में विस्तार द्वारा संचालित सेवा क्षेत्र के तेजी से बढ़ता क्षेत्र होने का अनुमान है.

श्री लंका

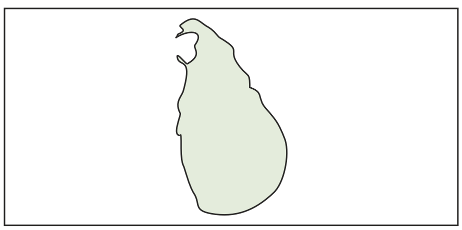

श्री लंका की वास्तविक जीडीपी वृद्धि को तेल की निम्न वैश्विक कीमतों से बढ़ती निजी खपत द्वारा समर्थन मिलने की उम्मीद है. पण्य बाजार घाटा ऊर्जा आयात में कमी के कारण 2015 में संकीर्ण होने की उम्मीद है. अर्थव्यवस्था 2015 में 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है जो 2014 में दर्ज की गई 7.4 प्रतिशत की दर से थोड़ी अधिक है. निजी खपत, जिसका सांकेतिक जीडीपी में लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा है, आर्थिक विस्तार का मुख्य इंजन बनी रहेगी. समग्र निवेश को देश के उत्तर तथा पूर्व में पुनर्निर्माण और साथ ही सेवा क्षेत्र में निवेश तथा शहरीकरण से हाउसिंग की बढ़ती मांग द्वारा समर्थन मिलेगा. उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में तीव्र वृद्धि से परिधान जैसे निर्यात उद्योगों को लाभ होगा. तेजी से बढ़ते पर्यटन, बीपीओ उद्योग के विकास और व्यापार तथा शिपिंग सेवाओं से उच्च आय द्वारा सेवा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.

ताज़ीकिस्तान

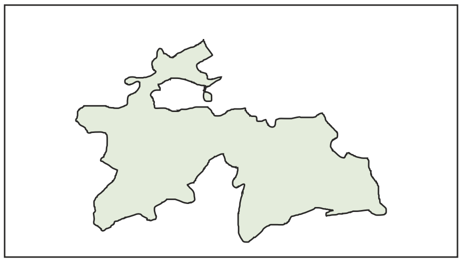

ताज़ीकिस्तान का वास्तविक जीडीपी 2013 में 7.4 प्रतिशत की तुलना में 2014 में 6.7 प्रतिशत बढ़ा. ताज़िक एल्यूमिनियम कंपनी (टोल्को), जो औद्योगिक उत्पादन का मुख्य संवाहक है, में उत्पादन 2014 में 42.2 प्रतिशत गिरा और यह सिर्फ 125,000 टन रहा. इसके अलावा, एल्युमिनियम की निम्न वैश्विक कीमतों का असर 2014 में आर्थिक वृद्धि पर पड़ा. ताजीकिस्तान रूसी आर्थिक मंदी द्वारा भी प्रभावित रहा है. विप्रेषण प्रवाह में तीव्र संकुचन और सोमोनी के तीव्र मूल्यह्रास से देशी मांग प्रभावित हुई. बाह्य मोर्चे पर, सोमोनी मुद्रा में गिरावट के बावजूद निर्यात पहली छमाही में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लगभग 16.6 प्रतिशत गिरा. एल्युमिनियम क्षेत्र के खराब प्रदर्शन और एल्युमिनियम की निम्न वैश्विक कीमतों से निर्यात आय प्रभावित होगी. रूस की स्थिति में सुधार और स्थूल आर्थिक विकास पर विनिमय दर के मूल्यह्रास के प्रभाव के कम होने के कारण 2016 में ताजीकिस्तान के आर्थिक कार्य-निष्पादन में सामान्य वृद्धि होने का अनुमान है.

चीनी युआन (सीएनवाई) : यूएसडी / सीएनवाई मई के 6.1972, मार्च के 6.1992, तथा दिसंबर के 6.2040 की तुलना में जून में 6.2008 पर बंद हुआ. दर में 25 आधार बिन्दु की कटौती बाजार के लिए पहले ही आ गई क्योंकि पीपल बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने जून में एक वर्ष की उधार तथा जमा दरों में पुन: कटौती करते हुए उसे क्रमश: 4.85 प्रतिशत तथा 2.00 प्रतिशत पर ला दिया. इसके अलावा, कुछ मानदंडों को पूरा करते हुए कृषि तथा/या एसएमई उधार वाले चुनिंदा बैंकों के लिए रिजर्व आवश्यकता अनुपात (आरआरआर) में 50 आधार बिन्दु की कटौती की गई और 28 जून से वित्त कंपनियों के लिए आरआरआर में 3 आधार बिन्दु की कमी की गई. जून 2015 के प्रारंभ में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में 13.2 प्रतिशत की गिरावट आने के बाद यह नीतिगत कार्रवाई की गई.

बाजार का मानना है कि उपर्युक्त कार्रवाई मुख्यत: तेजड़िया बाजार को समर्थन देने की सरकारी इच्छा द्वारा संचालित है. मुद्रा वृद्धि दर को 12 प्रतिशत के लक्ष्यित स्तर पर लाने के लिए पूंजी बहिर्वाह के बीच आरआरआर में कटौती अब भी आवश्यक है, जबकि दर में कटौती का औचित्य वृद्धि स्थिरता के प्रारंभिक संकेतों, दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति में संभावित वृद्धि तथा वास्तविक दरों को प्रभावित करने में बेंचमार्क दरों की घटती प्रभावशीलता के कारण कमजोर हो रहा है. पीबीओसी के बयान में, केन्द्रीय बैंक ने नोट किया है कि पूर्ववर्ती नीतियों ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है, नकदी तरलता सामान्यत: पर्याप्त है और निधीयन की लागत घट रही है जो ऐसी आक्रामक नीतिगत कार्रवाई के लिए कोई मजबूत तर्क प्रदान नहीं करती है. पीबीओसी अब भी उच्च वास्तविक ब्याज दरों को उच्च मानता है.

सरकार पूंजी बाजार को विस्तारित करने के लिए तेजड़िया बाजार बनाए रखने और बैंक उधार पर निर्भरता को कम करने के लिए उत्सुक दिखाई देती है. यद्यपि उस प्रयोजन के लिए मौद्रिक नीति के प्रयोग पर प्रश्न उठते हैं. सीएनवाई 30 जून 2005 को 6.20 यूएस डॉलर पर उद्धृत हो रहा था.

यूरो : जून के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो 1.0975 से मजबूत होकर 1.1142 हो गया. यूरोपीय केन्द्रीय बैंक की अधिशासी परिषद ने पुनर्वित्तपोषण तथा जमा दरों को क्रमश: 0.05 प्रतिशत तथा 0.20 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहने दिया.

9 मार्च से ईसीबी अपने आस्ति क्रय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभूतियों की खरीद कर रहा है जो कम से कम सितंबर 2016 तक जारी रहेगा जिसमें कुल 1.14 ट्रिलियन यूरो मूल्य यानि प्रति माह 60 बिलियन यूरो मूल्य की आस्तियां खरीदी गयीं.

ग्रीस के प्रमुख समाचार यूरो पर भारी प्रभाव नहीं डालते हैं. इसके बदले, बाजार ने इस प्रकार केवल 'अंतिम' निर्णय पर ध्यान दिया है : एक ऐसा निर्णय जो आईएमएफ के ऋण को चुकाने के लिए ग्रीस को 30 जून की तारीख नियत करता है. विस्तारित या नये बेलआउट निर्णय के जरिए या तो ग्रीस को रिडेम्प्शन के मार्ग पर जाने अथवा ग्रीस को चूक की ओर कदम बढ़ाने तथा मौद्रिक यूनियन की पूर्ण सदस्यता खोने की ओर ले जाता है.

10 वर्षीय जर्मन बॉड के प्रतिलाभ में जून के प्रारंभ में पुन: तेजी आई और जून के अंत में 27 आधार बिन्दु बढ़कर 0.76 प्रतिशत पर बंद हुआ. अंशत: प्रतिलाभ में उछाल ईसीबी के प्रेसिडेंट ड्रैघी की आगे बढ़ने में अनिश्चितता दर्शाता है, जिसमें यह अंतर्निहित है कि ईसीबी अपने इस व्यवहार को नहीं बदलेगा कि वह प्रतिलाभ को पुन: वापस निम्न स्तर पर लाने के उद्देश्य से क्यूई को कैसे कार्यान्वित करेगा. बढ़ी हुई अस्थिरता निश्चित रूप से इस कथ्य से संबंधित है कि ईसीबी ने वित्तीय बाजारों में विरूपण को बढ़ावा दिया है.

यूरो 30 जून, 2015 को 1.1135 यूएस डॉलर पर उद्धृत हो रहा था.

ब्राजीलियाई रियाल (बीआरएल) : रियाल जून में सामान्य रूप से मजबूत हुआ क्योंकि ब्राजीलियाई प्राधिकारियों ने मुद्रास्फीति को वापस नियंत्रण में लाने में सरकार तथा केन्द्रीय बैंक की क्षमता में नया विश्वास जागृत करने के प्रयास जारी रखे. इसमें दो घटनाक्रमों से कुछ हद तक सहायता मिली. पहला, जून में दरों को पुन: बढ़ाने के बावजूद बीसीबी (ब्राजीलियन सेंट्रल बैंक) ने अपनी मुद्रास्फीति रिपोर्ट में 2016 के लिए ऐसे मुद्रास्फीति पूर्वानुमान का प्रकटन किया जो लक्ष्य से ऊपर रहा, जबकि केन्द्रीय बैंक से जारी सूचनाओं में बाजार को सुझाव दिया गया कि जुलाई में दरों में वृद्धि की पुन: घोषणा की जाएगी. दूसरा, सरकार ने तब लगभग 4.5 प्रतिशत के मुद्रास्फीति के लक्ष्य के आस-पास की बैंक दरों की घोषणा की. +/- 2.0 पीपीटी बैंड को घटाकर तत्काल रूप से प्रभावी 3.0 -6.0 प्रतिशत के नये बैंड के साथ +/- 1.5 पीपीटी बैंड कर दिया गया है. राष्ट्रीय मौद्रिक परिषद, जो लक्ष्य निर्धारित करती है, ने भी राष्ट्रीय विकास बैंक द्वारा प्रभारित दीर्घावधि दर को 6.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया. लक्ष्य बैंड का संकीर्णन शायद अधिक प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका अर्थ यह हो सकता है कि ब्याज दरें भविष्य में लम्बी अवधि में ऊंची रहेंगी.

वार्षिक मुद्रास्फीति दर मई में बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो गई और सरकार द्वारा इस वर्ष के अंत तक 9.0 प्रतिशत तक पहुंच जाने की उम्मीद है. ये कार्यवाइयां आर्थिक कमजोरी को बढ़ा सकती हैं और राजकोषीय संभावनाओं पर अनिश्चितता और रेटिंग में गिरावट की आशंका बढ़ सकती है. प्राथमिक बजट घाटा मई माह में अपेक्षित स्तर से अधिक था. फेड ब्याज दरें बढ़ने पर बाजार पूर्वानुमान अवधि के दौरान वास्तविक मूल्यह्रास की प्रत्याशा करता है.

बीआरएल 30 जून, 2015 को 3.1020 यूएस डॉलर पर उद्धृत हो रहा था.

एक्ज़िम बैंक ने वर्ष 2014-15 में जोरदार कारोबार वृद्धि दर्ज की

वित्तीय निष्पादन

- ऋण पोर्टफोलियो : 15% की वृद्धि दर्ज करते हुए 86,953 करोड़ रुपये
- गैर-निधिक पोर्टफोलियो : 15% की वृद्धि दर्ज करते हुए 10,847 करोड़ रुपये
- बैंक की निवल संपदा : 19% की वृद्धि दर्ज करते हुए 9,902 करोड़ रुपये
- केन्द्र सरकार को पूँजी पर प्रतिफल : 28% की वृद्धि दर्ज करते हुए 433 करोड़ रुपये
- कुल व्यवसाय : 13% की वृद्धि दर्ज करते हुए 1,76,511 करोड़ रुपये
- जोखिम आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात : 15.34%
- निवल अनर्जक आस्तियां (एन पी ए) : 0.60% (80% प्रावधान सुरक्षा)

एक्ज़िम बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री यदुवेन्द्र माथुर ने गुरुवार, 30 अप्रैल 2015 को मुंबई में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में वर्ष 2014-15 के लिए बैंक के परिणामों की घोषणा की.

व्यवसाय एवं वित्तीय निष्पादन

- **ऋण-व्यवस्थाएं** बैंक ने भारत से परियोजनाओं, माल तथा सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुल 1,669.46 मिलियन यू एस डॉलर की (इस वर्ष 17 नई ऋण-व्यवस्थाएं) ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कीं. वर्तमान में 63 देशों में कुल 11.68 बिलियन यू एस डॉलर राशि की 194 ऋण-व्यवस्थाएं उपभोग के लिए उपलब्ध हैं जबकि कई ऋण-व्यवस्थाएं बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं.
- **परियोजना निर्यात संविदाएं** वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान एक्ज़िम बैंक की सहायता से 56 कंपनियों ने 40 देशों में 105 परियोजना निर्यात संविदाएं प्राप्त कीं जिनका कुल मूल्य रुपये 49,781 करोड़ रहा. यथा 31 मार्च, 2015 को एशिया, अफ्रीका तथा सी आई एस क्षेत्र के 81 देशों में 139 भारतीय कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही 414 परियोजना निर्यात संविदाओं को बैंक द्वारा सहायता दी गई जिनका मूल्य रुपये 1,89,736 करोड़ (लगभग 30.45 बिलियन यू एस डॉलर) रहा.
- **क्रेता-ऋण** राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (बी सी-एन ई आई ए) - बैंक ने बी सी-एन ई आई ए के अंतर्गत कुल 4.40 बिलियन यू एस डॉलर राशि की 18 परियोजनाओं के लिए 2.68 बिलियन यू एस डॉलर की ऋण मंजूरी दी है.
- **विदेशी निवेश** बैंक द्वारा 35 कंपनियों को 11 देशों में उनके समुद्रपारीय निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए कुल 5,544 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई. एक्ज़िम बैंक द्वारा अब तक 91 देशों में 530 कंपनियों द्वारा स्थापित 533 उद्यमों को विदेशी निवेश के लिए कुल 43,210 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है.
- **कर पूर्व लाभ एवं कर पश्चात लाभ** वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक का (पीबीटी) कर पूर्व एवं कर पश्चात लाभ (पीएटी) क्रमशः रुपये 1,135 करोड़ तथा रुपये 726 करोड़ रहा.

संसाधन/ट्रेजरी

- वर्ष के दौरान बैंक ने विविध परिपक्वता अवधि वाली उधारियों के रूप में रुपये 18,343 करोड़ के रुपया संसाधन तथा रुपये 13,012 करोड़ मूल्य के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाए.
- बैंक को निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग प्रदान की गई है जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समतुल्य की रेटिंग है. यथा 31 मार्च, 2015 को बैंक को मूडीज द्वारा बीएए 3 (सकारात्मक) रेटिंग, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स द्वारा बीबीबी– (स्थिर), फिच द्वारा बीबीबी– (स्थिर) तथा जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (जेसीआरए) द्वारा बीबीबी+ (स्थिर) रेटिंग प्रदान की गई है. बैंक के घरेलू रुपया ऋण लिखतों को रेटिंग एजेंसियों क्रिसिल तथा इक्रा द्वारा 'एएए' जैसी उच्चतम रेटिंग प्रदान की जाती रही है.

अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में नए बेंचमार्क

- वर्ष के दौरान बैंक ने भारत का पहला यू एस डॉलर मूल्यांकित ग्रीन बॉंड जारी किया. 5 वर्षीय अवधि तथा 500 मिलियन यू एस डॉलर मूल्य के इस बॉंड को 3.2 गुना अभिदान मिला.
- बैंक ने समुराई बॉंड जारी कर 20 बिलियन जापानी येन की राशि जुटाई. बैंक ने जेबीआईसी गेट सुविधा के इतिहास में एक प्रतिशत से भी कम दर पर सबसे टाइट स्प्रेड हासिल किया.

नई पहलें

- **ईरान को निर्यात विकास निधि (ई डी एफ) सुविधा प्रदान की गईः** रणनीतिक उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मदद हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एक्ज़िम बैंक अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित ई डी एफ एक विशेष निधि है, जिसका प्रबंध एक्ज़िम बैंक द्वारा किया जाता है. हाल ही में भारत से ईरान को माल तथा सेवाओं के निर्यात करने हेतु ईरानी बैंकों को क्रेता ऋण सुविधा के तहत रुपये 900 करोड़ की ईडीएफ की पहली ऋण सुविधा प्रदान की गई है. इसे ईरान सरकार की संप्रभु गारंटी प्राप्त है.
- **पड़ोसी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए विशेष ऋण सुविधाः** ये सुविधाएं दो प्रकार की होंगी - रियायत दर पर एवं वाणिज्यिक दर पर; तथा इसके अंतर्गत परियोजनाओं को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान की जाएगी. प्रधान मंत्री द्वारा नवंबर 2014 में काठमांडू में की गई घोषणा के अनुसार इसे परिचालित किया जा रहा है.
- **सी एल एम वी देशों में व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु परियोजना विकास कंपनीः** भारत सरकार के 'एक्ट ईस्ट इनिशिएटिव' के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक द्वारा सी एल एम वी देशों में एक मिशन भेजा गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक परियोजना विकास कंपनी की स्थापना की जा रही है; बाद में परियोजना विकास एवं सुगमीकरण फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी.
- **अफ्रीका में परियोजना विकास कंपनीः** एक्ज़िम बैंक, आई एल एंड एफ एस, ए एफ डी बी तथा एस बी आई ने मिलकर अफ्रीका में मॉरिशस आधारित एक परियोजना विकास कंपनी स्थापित की है. कंपनी द्वारा सहायता के लिए ऊर्जा क्षेत्र में दो परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं, जिनमें से एक तंजानिया में तथा दूसरी नाइजीरिया में है.

संकेतक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
जीडीपी (वर्तमान मूल्यों पर, बिलियन यूएस डॉलर)	**1365.4**	**1708.5**	**1843.2**	**1835.8**	**1875.9**	**2050.6^{f}**	**2187.7^{f}**
	1146.7	**1411.7**	**1498.5**	**1468.4**	**1476.4**	**1587.9^{e}**	**-**
वास्तविक जीडीपी वृद्धि (%)	**8.6**	**8.9**	**6.7**	**5.1****	**6.9****	**7.4^{p}****	**7.6$^{@}$**
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	0.8	8.6	5.0	-0.2**	3.7**	0.2^{p}**	-
उद्योग	9.2	7.6	7.8	2.9**	4.5**	6.1^{p}**	-
सेवाएं	10.5	9.7	6.6	8.7**	9.1**	10.2^{p}**	-
जीडीपी में क्षेत्रगत हिस्सा (%)							
कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	14.6	14.6	18.9**	17.7**	17.2**	16.1^{p}**	-
उद्योग	28.3	27.9	32.9**	32.3**	31.7**	31.4^{p}**	-
सेवाएं	57.1	57.5	48.2 **	50.0**	51.1**	52.5^{p}**	-
जनसंख्या (मिलियन)	**1190.7**	**1210.2**	**1230.0**	**1250.2**	**1270.6**	**1291.4^{e}**	**-**
	12.2	**10.8**	**10.3**	**10.2**	**9.5**	**6.4**	**5.1 (**
मुद्रास्फीति की दर (डब्ल्यूपीआई, वार्षिक औसत %)	**3.8**	**9.6**	**8.9**	**7.4**	**6.0**	**2.0**	**-2.40 (जून '15)**
सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का %)	**6.5**	**4.8**	**5.8**	**4.9**	**4.4**	**4.1^{e}**	**3.9^{e}**
विनिमय दर (रु. / यूएस डॉलर, औसत)	47.4	45.6	47.9	54.4	60.5	61.1	63.75 (जून 30,'15)
विनिमय दर (रु. / यूरो, औसत)	67.1	60.2	65.9	70.1	81.2	77.5	71.20 (जून 30,'15)
निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**178.8**	**249.8**	**306.0**	**300.4**	**314.4**	**309.6**	**66.7 (अप्रैल-जून '15)**
% परिवर्तन	*-3.5*	*39.8*	*22.5*	*-1.8*	*4.7*	*-1.5*	-16.2^
तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**28.2**	**36.4**	**56.7**	**60.9**	**63.2**	**56.7**	**8.2 (अप्रैल-जून '15)**
% परिवर्तन	*2.3*	*29.0*	*55.9*	*7.3*	*3.8*	*-10.2*	-51.0^
गैर-तेल निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)	**150.6**	**213.4**	**249.2**	**239.5**	**251.2**	**252.8**	**58.5 (अप्रैल-जून '15)**
% परिवर्तन	*-4.6*	*41.8*	*16.8*	*-3.9*	*4.9*	*0.6*	-6.9^
आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**288.4**	**369.8**	**489.3**	**490.7**	**450.2**	**447.5**	**99.0 (अप्रैल-जून '15)**
% परिवर्तन	*-5.1*	*28.2*	*32.3*	*0.3*	*-8.3*	*-0.6*	-12.5^
तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**87.1**	**106.0**	**155.0**	**164.0**	**164.8**	**138.3**	**24.7 (अप्रैल-जून '15)**
% परिवर्तन	*-7.0*	*21.6*	*46.2*	*5.9*	*0.4*	*-16.0*	-38.9^
गैर-तेल आयात (बिलियन यूएस डॉलर)	**201.2**	**263.8**	**334.3**	**326.7**	**285.4**	**309.3**	**74.3 (अप्रैल-जून '15)**
% परिवर्तन	*-4.2*	*31.1*	*26.7*	*-2.3*	*-12.6*	*8.4*	2.2^
व्यापार शेष (बिलियन यूएस डॉलर)	**-109.6**	**-120.0**	**-183.3**	**-190.3**	**-135.8**	**-138.0**	**32.3 (अप्रैल-जून '15)**
सेवा निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)*	**96.0**	**124.6**	**140.9**	**145.7**	**151.5**	**155.4**	**24.9 (अप्रैल-जून '15)**
साफ्टवेयर निर्यात (बिलियन यूएस डॉलर)*	49.7	53.1	62.2	65.9	69.4	73.1	-
सेवा आयात (बिलियन यूएस डॉलर)*	**60.0**	**80.6**	**76.9**	**80.8**	**78.5**	**79.8**	**13.6 (अप्रैल-मई '15)**
सेवा शेष (बिलियन यूएस डॉलर)*	36.0	44.0	64.0	64.9	73.0	75.6	11.3 (अप्रैल-मई '15)
चालू खाता शेष (बिलियन यूएस डॉलर)*	**-38.4**	**-47.9**	**-78.2**	**-87.8**	**-32.4**	**-27.5**	**-**
जीडीपी के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष (%)	*-2.8*	*-2.8*	*-4.2*	*-4.8*	*-1.7*	*-1.3*	-
विदेशी मुद्रा भंडार (बिलियन यूएस डॉलर)	**279.1**	**304.8**	**294.4**	**292.0**	**304.2**	**341.6**	**355.2 (जून 26, '15)**
विदेशी ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	**260.9**	**317.9**	**360.8**	**409.4**	**446.3**	**475.8**	**-**
जीडीपी की तुलना में विदेशी ऋण अनुपात (%)	18.3	18.2	20.9	22.3	23.6	23.8	-
अल्पावधि ऋण (बिलियन यूएस डॉलर)	52.3	65.0	78.2	96.7	91.7	84.7	-
अल्पावधि ऋण / कुल ऋण (%)	20.1	20.4	21.7	23.6	20.5	17.8	-
कुल ऋण चुकौती अनुपात (%)	5.8	4.4	6.0	5.9	5.9	7.5	-
एफडीआई (बिलियन यूएस डॉलर)	**37.7**	**36.0**	**46.6**	**34.3**	**36.0**	**44.3**	**9.5 (अप्रैल-मई '15)**
जी डी आर / ए डी आर एस (बिलियन यू एस डॉलर)	3.3	2.0	0.6	0.2	0.02	-	1.3 (अप्रैल-मई '15)
एफ आई आई एस (निवल) (बिलियन यू एस डॉलर)	29.0	29.4	16.8	27.6	5.0	40.9	0.3 (अप्रैल-मई '15)
एफ डी आई प्रवाह (बिलियन यू एस डॉलर)	**15.1**	**17.2**	**10.9**	**7.1**	**9.2**	**1.7**	**0.9 (अप्रैल-मई '15)**
मेमो मदें :	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014^{f}**	**2015^{f}**	**2016^{f}**
वैश्विक जीडीपी (% परिवर्तन)	**5.4**	**4.1**	**3.4**	**3.4**	**3.4**	**3.3**	**3.8**
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	3.1	1.7	1.2	1.4	1.8	2.1	2.4
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	7.4	6.2	5.2	5.0	4.6	4.2	4.7
विश्व पण्य व्यापार (परिमाण, % परिवर्तन)	**14.3**	**6.9**	**2.5**	**3.1**	**3.0**	**3.5**	**4.7**
विश्व पण्य निर्यात (ट्रिलियन यूएस डॉलर)	**15.0**	**18.0**	**18.2**	**18.6**	**18.8**	**17.3**	**18.4**
विश्व पण्य निर्यात के मूल्य में वृद्धि (%)	**21.7**	**20.0**	**1.0**	**2.3**	**1.0**	**-8.1**	**6.5**

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, विभिन्न अंक : केन्द्रीय बजट, भारतीय रिजर्व बैंक मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्ट एवं साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक, वित्त मंत्रालय, सीएसओ, ईआईयू, नैस्कॉम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ), डब्ल्यूईओ, आईएमएफ.

टिप्पणी : इ - भारत सरकार के अनुमान, पी – भारत सरकार के अग्रिम अनुमान, एफ – आईआईएफ पूर्वानुमान, - उपलब्ध नहीं, * - बजट 2015-16 अनुमान, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2015-16 में 8 से 8.5 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान, ** संशोधित आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार आंकड़े, ***2009-10 से आंकड़े आईएमएफ भुगतान संतुलन मैनुअल में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर भुगतान संतुलन के आंकड़ों के मानक प्रस्तुतीकरण के नये फॉर्मेट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए हैं. @ आईआईएफ अनुमान, ^ % परिवर्तन गत वर्ष की अनुरूपी अवधि की तुलना में है.

चार्ट 1 : भारत का निर्यात : मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

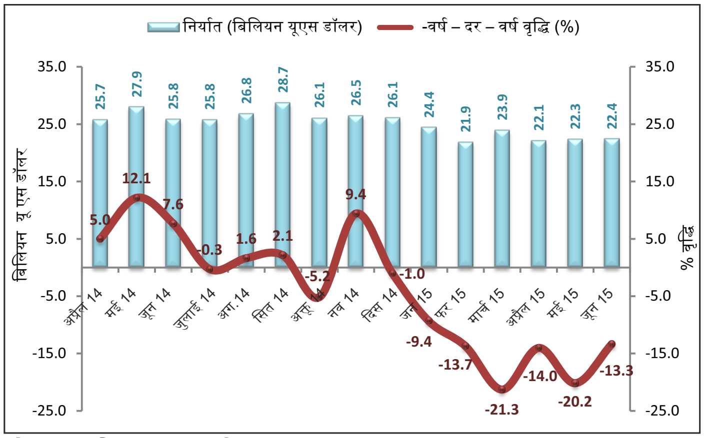

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 2 : भारत का आयात : मासिक एवं प्रतिशत परिवर्तन

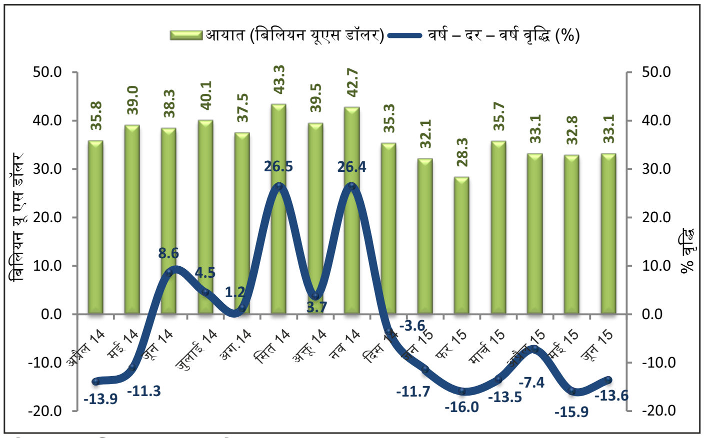

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 3 : 2014-15 में भारत की निर्यात संरचना

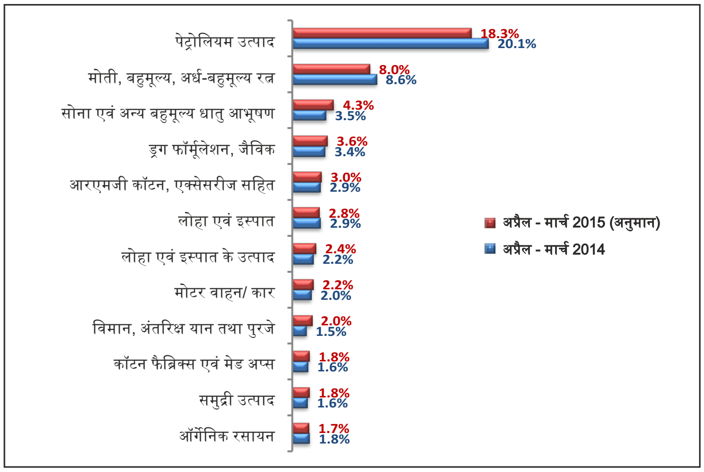

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 4 : 2013-14 में भारत की आयात संरचना

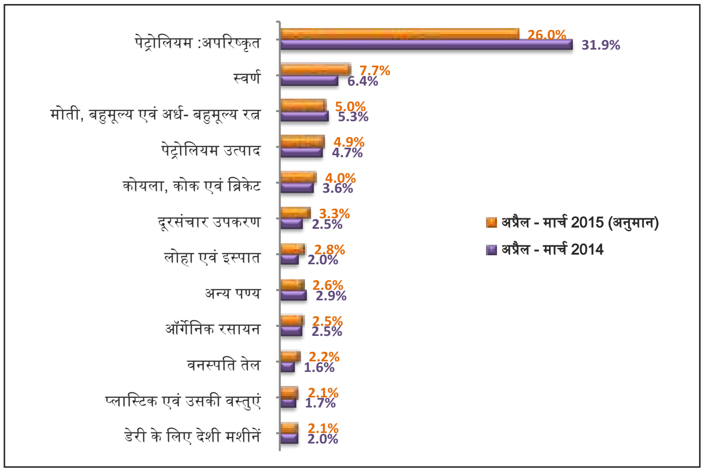

स्रोत : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

चार्ट 5 : विश्व पण्य निर्यात में भारत का हिस्सा

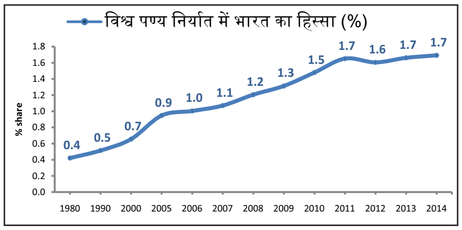

टिप्पणियां :

1) जर्मनी को प्रतिस्थापित करते हुए चीन 2009 में अग्रणी वैश्विक निर्यातक के रूप में उभरा. 2) भारत 2014 में 19 वां सबसे बड़ा वैश्विक निर्यातक बनकर उभरा है जो 2013 के 20 वें, 2007 के 26 वें और 2000 के 32 वें स्थान से ऊपर है.

स्रोत : डब्ल्यूटीओ (30 जून 2015 को आकलित स्थिति)

चार्ट 6 : विश्व सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा

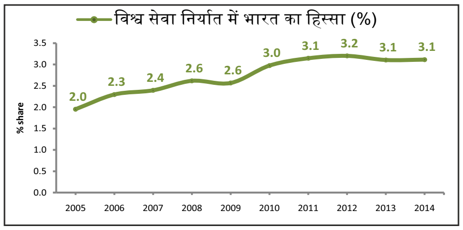

टिप्पणियां :

1) भारत वर्ष 2014 में छठां सबसे बड़ा वैश्विक सेवा निर्यातक बनकर उभरा है जो 2009 के 9 वें और 2005 के 11 वें स्थान से ऊपर है.

स्रोत : डब्ल्यूटीओ (30 जून 2015 को आकलित स्थिति)

इसमें प्रकाशित समाचार और जानकारी ऐसे विभिन्न स्रोतों/ माध्यमों से एकत्रित की गई है जो अपने आप में प्रमाणिक हैं. प्रकाशित सामग्री की प्रामाणिकता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती गई है फिर भी इस प्रकार की जानकारी की प्रमाणिकता और यथातथ्यता की कोई जिम्मेदारी एक्ज़िम बैंक की नहीं है.

नोटः भारतीय रुपये का उल्लेख करोड़ और लाख में किया गया है.
1 करोड़ः 10 मिलियन
1 लाखः 100 हजार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक
केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र कॉम्प्लेक्स,
कफ़ परेड, मुंबई- 400 005
दूरभाषः +91-22-2217 2600
फैक्सः +91-22-2218 2572
ई-मेलः ccg@eximbankindia.in
वेबसाइटः www.eximbankindia.in

व्यापार एवं साझेदारी अवसर

व्यापार अवसर

हाथ से बुने कपड़े

अल्मोड़ा उत्तराखंड के 32 गांवों की 1500 महिला कारीगरों के साथ काम करनेवाली महिलाओं की बुनकर सोसाइटी. यह सोसाइटी हिमालय की प्राचीन हस्तशिल्प कलाओं पर आधारित हाथ से बुने और सिले कपड़े तैयार करती है.

बर्फ बनाने की मशीन

एक विनिर्माता जो बर्फ (आइस) बनाने की मशीन निर्माण करता है. यह मशीन विभिन्न उद्योगों जैसे होटेल्स, समुद्री खाद्य प्रोसेसिंग, रसायन तथा डाई उत्पादक उद्योगों के लिए उपयुक्त है.

वाटर पंप तथा मोटर

एक आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणित कंपनी जो स्टार एक्सपोर्ट हाउस भी है, सबमर्सिबल स्टेनलेस स्टील पम्प तथा मोटर बनाती है. कंपनी विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त पंपिंग सॉल्यूशन तैयार करती है.

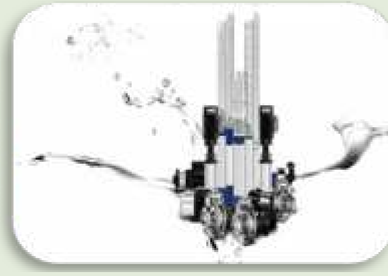

पॉली प्रोपिलीन मैट

हर तरह के उपयोग के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकीयुक्त विभिन्न प्रकार के डिजाइनों वाले फ्लोर मैट्स (चटाइयां) तैयार करने वाली कंपनी. आधुनिक डिजाइन वाले यह कार्पेट धुले जा सकते हैं (वाशेबल) हैं तथा इनका रख-रखाव बहुत ही आसान है.

रबड़ मोल्डेड कंपोनेंट

ऑटोमोटिव उद्योग में अनुप्रयोग के लिए कस्टम मेड रबड़ मोल्डेड कंपोनेंट एवं पार्ट्स के प्रमुख विनिर्माता.

मीटरिंग सॉल्यूशन

एक आई एस ओ 9001:14001 प्रमाणित कंपनी जो विद्युत क्षेत्र के विभिन्न व्यवसाय वर्टिकलों में है तथा ऊर्जा क्षेत्र को उच्च नवोन्मेषी एवं स्थायी सॉल्यूशन प्रदान करता है. ये वर्टिकल हैं- मीटरिंग सॉल्यूशन, पॉवर बैकअप एवं सोलर सॉल्यूशन तथा इंजीनियरिंग निर्माण एवं टनकीं संविदा आदि.

साझेदारी के अवसर

निवेश के अवसर

(i) मोजाम्बिक की एक कंपनी ई पी सी के लिए कच्चे माल जैसे नाइट्रीक एसिड तथा उर्वरक जैसे अमोनियम नाइट्रेट, एन पी के एवं डी ए पी के उत्पादन के लिए औद्योगिक उर्वरक संयंत्र लगाने के लिए तकनीक आपूर्तिकर्ता और/ अथवा संभाव्यता ईक्विटी निवेशक के रूप में इच्छुक भारतीय कंपनियों की तलाश में है.

(ii) म्यांमार की एक कंपनी म्यांमार में सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए मैन्युफैक्चरिंग सुविधा की स्थापना के लिए भारतीय संयुक्त उद्यम साझेदार की तलाश कर रही है.

निर्यात के अवसर

- ईजिप्ट के आयातक को भारत से अलग-अलग आकार में कटे हुए प्री-पेंटेड गालवेनाइज्ड स्टील कॉयल चाहिए.
- यू एस की एकई-कॉमर्स कंपनी को करूर, तमिल नाडु से हथकरघे से तैयार किए गए गृह सज्जा उत्पादों को आयात करने की इच्छुक है.
- रूस की फुटकर सुपरमार्केट को ताजे प्याज एवं आलू जैसे उत्पादों की आवश्यकता है.

इच्छुक पार्टियां नीचे दिए गए संपर्क विवरण पर विपणन सलाहकारी सेवाएं समूह से संपर्क कर सकते हैं.

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें- फोनः 2217 2600 एक्सटेंशनः 2707. फैक्सः 2218 8268 ई-मेलः mas@eximbankindia.in